साप्ताहिक हिन्दी और उर्दू समाचार पत्र

जयपुर से प्रकाशित

उम्मीद की एक नई रोशनी

आवाज़ ए तसनीम

آوازِ تسنیم

tasneemtv.official@gmail.com

PRGI No. RJBIL/25/A1815

www.tasneemtv.com | वर्षः 02 / अंकः 14 | जयपुर, सोमवार, 19 अक्टूबर , 2026 | पृष्ठ : 8 | मूल्यः 2 रूपए | प्रातः कालीन



मुख्यमंत्री की नवरात्र पर महिला सुरक्षा को समर्पित बड़ी सौगात, नवीन 100 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का शुभारंभ

कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स,सीएलजी और सुरक्षा सखी बनें जनजागरुकता की महत्वपूर्ण कड़ी:मुख्यमंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी संस्कृति में शक्ति की आराधना का पावन पर्व नवरात्र मातृ शक्ति के सम्मान और सुरक्षा सर्वोपरि की सीख देता है। इसी भावना के साथ राज्य सरकार महिला एवं बालिका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, ताकि वे बिना किसी भय के शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक गतिविधियों में और आगे बढ़ सकें।

नवरात्र पर मुख्यमंत्री की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स को सौगात

मुख्यमंत्री ने कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें प्रतिमाह थाने एवं पुलिस चैकी में पदस्थापित कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल और एएसआई की तरह निश्चित यात्रा भत्ता देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का उद्देश्य



केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि अपराधों की रोकथाम, असामाजिक तत्वों में कानून का भय और महिलाओं में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना पैदा करना भी है।

मुख्यमंत्री रविवार को कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में नवीन कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स एवं महिला यूथ सीएलजी सदस्यों के साथ संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि उनके सम्मान, स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और समान अवसरों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मुख्यमंत्री ने कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स की महिला पुलिसकर्मियों से संवेदनशीलता, कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और साहस के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तीकरण को नई दिशा मिली है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान से लेकर उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुद्रा योजना और लखपति दीदी जैसी पहलों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। वहीं, राज्य सरकार द्वारा भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आधी आबादी को उनका पूरा हक देना सुनिश्चित किया जा रहा है।

अब तक 55 हजार से अधिक असामाजिक तत्वों पर हुई कार्रवाई –

मुख्यमंत्री ने कहा कि कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स और महिला यूथ सीएलजी सदस्यों का फील्ड में प्रभावी असर नजर आ रहा है। यही कारण है कि वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2026 में महिला अत्याचार के प्रकरणों में लगभग 48 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है तथा महिला अत्याचार संबंधी प्रकरणों में अनुसंधान का औसत समय घटकर 48 दिन रह गया है। उन्होंने कहा कि कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स द्वारा 55 हजार से अधिक असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 50 लाख महिलाओं एवं बालिकाओं को कानून और 18 लाख से अधिक को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरुक किया गया है। इसी प्रकार लगभग 16 लाख 70 हजार से अधिक महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी दिया गया है।

एक नजर

नाशवान खाद्य पदार्थों को लेकर एफएसएसएआई सख्त, कारोबारियों के लिए जारी की नई एडवाइजरी

नई दिल्ली(एजेंसी)। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खोया, पनीर, मांस, मछली और अन्य नाशवान खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रविवार को एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। प्राधिकरण ने कहा है कि ऐसे खाद्य उत्पादों को पूरी सप्लाई चेन में निर्धारित तापमान पर ही संभाला, संग्रहीत और परिवहन किया जाना चाहिए। एफएसएसएआई ने सभी खाद्य कारोबार संचालकों (एफबीओ) को स्वच्छता और तापमान नियंत्रण संबंधी मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।



विपक्ष की ओछी हरकतें बताती हैं कि भारत को एक मजबूत नेतृत्व की क्यों जरूरत है: कंगना रनौत

रायपुर(एजेंसी)। अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत छत्तीसगढ़ के रायपुर में शनिवार की रात को ढोलिडा 2026 में हिस्सा लिया। ढोलिडा 2026 शहर के सबसे बड़े नवरात्र रास गरबा आयोजनों में से एक है।

अभिनेत्री ने रविवार को कोलकाता भगदड़ हादसा, विपक्ष के रिजीम चेंज बयान और छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर बात की। कंगना रनौत ने अष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रायपुर में पहली बार गरबा में शामिल होने का अनुभव बहुत ही शानदार रहा। गुजरात से निकलकर गरबा अब पूरे देश में हो रहा है, जो अच्छी पहल है।



पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सरकार ने नारीशक्ति को बनाया यूपी की प्रगति का सक्रिय भागीदार : सीएम योगी

लखनऊ(एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने नारीशक्ति को प्रदेश की प्रगति का सक्रिय भागीदार बनाते हुए सुरक्षा, सम्मान, पोषण, शिक्षा और आर्थिक स्वावलंबन के अवसरों का विस्तार किया है। शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां महागौरी का स्मरण किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, शांति, पवित्रता और करुणा की प्रतीक मां महागौरी की आराधना हमें स्मरण कराती है कि समाज की वास्तविक उन्नति तभी संभव है।

जेएनयू में निकला पथ संचलन

नई दिल्ली, आरएनएन। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में आरएसएस ने शनिवार को पहली बार पंथ संचलन आयोजित किया। इस आयोजन को लेकर अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने रविवार को कहा कि जेएनयू में इसका आयोजन होना एक अच्छी शुरुआत है।

साथ ही उन्होंने पोस्टरों में विपक्षी नेताओं को देवी-देवताओं के रूप में दिखाए जाने पर आपत्ति भी जताई और इसे अपराध करार दिया। इंद्रेश कुमार ने रविवार को कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर लोग अराजकता छोड़कर लोकतंत्र को अपनाते हैं, तो जेएनयू के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन होना कोई हैरानी की बात नहीं है।

मौत के बाद दूसरे ब्रह्मांड में चली जाती है 'आत्मा'

● नई दिल्ली

वैज्ञानिक डॉ. रॉबर्ट लैंजा की किताब बायोसेंट्रिज्मः हाउ लाइफ एंड कॉन्शसनेस आर द कीज टू अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द यूनिवर्स ने इंटरनेट पर काफी चर्चा पैदा की है। इसमें दावा किया गया है कि शरीर की मौत के साथ जीवन खत्म नहीं होता और चेतना हमेशा बनी रह सकती है। यानी कुछ लोग इसे आत्मा भी कहते हैं। लैंजा के अनुसार चेतना ब्रह्मांड की मूलभूत चीज है।

भौतिक ब्रह्मांड चेतना से पैदा होता है, न कि उलटा। यह सिद्धांत वैज्ञानिक समुदाय में विवादास्पद है क्योंकि यह मुख्यधारा की भौतिकी से अलग खड़ा है। डॉ. रॉबर्ट लैंजा चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं. पहले स्टेम सेल तथा लुप्तप्राय प्रजातियों की क्लोनिंग पर काम कर चुके हैं, बाद में उन्होंने भौतिकी, क्वांटम यांत्रिकी और एस्ट्रोफिजिक्स की ओर रुख किया। उनके



बायोसेंट्रिज्म सिद्धांत के अनुसार जीवन और चेतना ब्रह्मांड की नींव हैं। ब्रह्मांड के नियम और स्थिर जीवन के अनुकूल दिखते हैं, जिससे लगता है कि बुद्धिमत्ता पदार्थ से पहले मौजूद थी। लैंजा कहते हैं कि स्थान और समय वस्तुएं नहीं बल्कि हमारी समझ के औजार हैं। हम इन्हें कछुए के खोल की तरह साथ लेकर चलते हैं। जब शरीर (खोल) खत्म होता है तो भी चेतना बनी रहती है।

क्वांटम यांत्रिकी थ्योरी पर संदेह

क्वांटम यांत्रिकी में गैर-स्थानीयता और मल्टीवर्स व्याख्याएं मौजूद हैं, लेकिन वे चेतना के जीवित रहने या दूसरे ब्रह्मांड में जाने को साबित नहीं करतीं। ज्यादातर भौतिक विज्ञानी चेतना को मस्तिष्क की जैविक प्रक्रिया मानते हैं, कोई प्रत्यक्ष प्रयोग या सबूत नहीं है जो लैंजा के दावे की पुष्टि करे। यह सिद्धांत दार्शनिक और स्पेकुलेटिव ज्यादा है। वैज्ञानिक पद्धति अनुभवजन्य सबूतों पर टिकी होती है, जबकि यहां व्याख्या और संभावनाओं पर जोर है। फिर भी यह चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जीवन, मौत और ब्रह्मांड के बारे में गहरे सवाल उठाती है। लोग अमर होने की इच्छा रखते हैं, इसलिए ऐसे विचार लोकप्रिय हो जाते हैं।

क्वांटम चेतना और निकट-मृत्यु अनुभव

डॉ. स्टुअर्ट हैमेरोफ जैसे कुछ शोधकर्ताओं का भी जिक्र आता है। उनके अनुसार हृदय रुकने पर माइक्रोट्यूबुल्स में क्वांटम जानकारी नष्ट नहीं होती बल्कि ब्रह्मांड में फैल जाती है। अगर मरीज को बचा लिया जाए तो यह जानकारी वापस आ सकती है और निकट-मृत्यु अनुभव होता है। अगर नहीं बचाया गया तो यह जानकारी शरीर के बाहर बनी रह सकती है, शायद आत्मा के रूप में। लैंजा इसे दूसरे ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। यह व्याख्या निकट-मृत्यु अनुभव, शरीर से बाहर की यात्रा और पुनर्जन्म जैसी घटनाओं को धार्मिक आस्था के बिना समझाने की कोशिश करती है। चेतना की ऊर्जा किसी स्तर पर बनी रहती है और बाद में किसी दूसरे शरीर में जा सकती है। बायोसेंट्रिज्म रोचक और आशा देने वाला विचार है, लेकिन यह मुख्यधारा की विज्ञान में स्थापित नहीं है।

मुझ पर केस किया तो मामला कानूनी हो जाएगा : राहुल

कहा : हर राज्य में वोट चोरी की बात कहता हूं; ज्ञानेश जानते हैं कीमत चुकानी होगी

पणजी।

राहुल गांधी ने रविवार को गोवा में कहा कि मैं हर राज्य से कहता हूं प्रधानमंत्री वोट चोरी करते हैं। लेकिन मुझ पर कोई केस दर्ज नहीं होता। क्योंकि, ये जानते हैं कि अगर केस हुआ तो मामला कानूनी हो जाएगा और ये फंस जाएंगे। दिल्ली में हम कुछ ही समय में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री से निपट लेंगे। काम जारी है। सरकार की कार्यकाल की अंतिम तारीख आने वाली है। आपने देखा है कि आजकल प्रधानमंत्री सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ये जानते हैं कि देश का युवा इनके खिलाफ खड़ा हो गया है। राहुल कांग्रेस के जनसंपर्क अभियान गोय राखोन यात्रा में शामिल होने गोवा पहुंचे थे। यहां कांग्रेस की 28 दिन लंबी यात्रा का समापन हुआ है। राहुल का पिछले 4 सालों में यह पहला गोवा दौरा है। इससे पहले 2022 में वह यहां आए थे। गोवा में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव हैं।

राहुल की भाषण, 4 बड़ी बातें

1. हर शिक्षा व्यवस्था में आरएसएस के लोग: पूरी दुनिया मानती थी कि भारत का शिक्षा व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ प्रतिमान का था। लेकिन, आज दिल्ली में विद्यार्थियों को ही मारा जा रहा है। हर शिक्षा व्यवस्था में इन्होंने भाजपा और आरएसएस के लोग बैठाए हुए हैं।
2. कांग्रेस भ्रष्टाचार मॉडल खत्म करेगी: उच्च तकनीक वाला भ्रष्टाचार, जमीन का भ्रष्टाचार ये यहां करते हैं। जैसे पहले गुजरात में नरेंद्र मोदी का मॉडल था। वैसे



ही गोवा में भ्रष्टाचार का मॉडल है। इसे सिर्फ कांग्रेस ही खत्म कर सकती है।
3. देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी गोवा में: पहले महायोजना था, महायोजना को रद्द कर दिया। इनका यही काम है कि पैसा कैसे बनाए। इनका यही काम है। गोवा की जनता को लूटने का, आपकी जमीन छीनकर अरबपतियों को देने का।
4. गोवा में सरकार आपकी जमीन छीन रही: गोवा देश में सबसे सुंदर जगह है, सबसे अच्छा संस्कृति है। लेकिन यहां भी सरकार आपकी जमीन छीनकर गोवा के जो बाहर के लोग हैं उनको करोड़ों में बेचती है। पहले महायोजना था, महायोजना को रद्द कर दिया। इनका यही काम है कि पैसा कैसे बनाए।

युवक झुलसा

जयपुर में 33 हजार केवी की लाइन से झुलसा युवक

शराब पीकर बिजली पोल पर चढ़ा,पुलिस कॉन्स्टेबल ने बचाई जान;अधजली हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया

जयपुर(नि.सं.)। जयपुर में आज सुबह एक युवक शराब के नशे में बिजली की लाइन पर चढ़ गया, जिससे युवक का शरीर झुलस गया। अर्द्धजली हालत में वह पोल पर ही झुलसकर अटक गया। इस दौरान युवक मदद की गुहार लगा रहा था। खोराबीसल थाना के कॉन्स्टेबल ने अपनी जान जोखिम में डाल चालू लाइन पर चढ़कर स्थानीय लोगों की मदद से नीचे उतारा।

पुलिस ने अधझुलसे युवक को कांवटिया हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। पीड़ित की पहचान मोतीलाल (50) निवासी सागर मध्य प्रदेश, वर्तमान में बावड़ी तरहटी (कच्ची बस्ती) खोरा बीसल के रूप में हुई है। वह मजदूरी का काम करता है।

मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी का शक्ति पथ संचलन

मेड़ता सिटी।विश्व हिन्दू परिषद के पूर्व अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक जी सिंहल के जन्म शताब्दी वर्ष में नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी के अवसर पर आज कृष्ण भक्त मीरां की नगरी मेड़ता में शक्ति स्वरुपा नारी शक्ति का पथ संचलन कार्यक्रम संपन्न हुआ । जिसमें नारी शक्ति के साहस, शौर्य और अनुशासन में एकजुटता का दृश्य देख कर शहरवासी गदगद् हो गये । विश्व हिन्दू परिषद के मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी मेड़ता की ओर से निकाले गए शक्ति पथ संचलन में निर्धारित गणवेश धारण किये बहनों ने तथा मातृशक्ति ने अनुशासित कदम ताल के साथ , घोष की धुन पर शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दिया । हाथों में दंड लिए उत्साहपूर्वक आगे बढ़ती शक्ति स्वरुपा मातृशक्ति







, और स्वागत में गगनभेदी जयघोष ने पूरे मीरां नगरी में जोश भर दिया । शक्ति पथ संचलन का नगरवासियों ने जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया । संचलन के अंत में देवी दुर्गा का चित्र बहनों को आशीर्वाद एवं अन्याय का संहार करने की प्रेरणा दे रहा था । शक्ति संचलन प्रारंभ होने से पूर्व तीन बजे से घांची समाज पंचायत भवन में दुर्गा वाहिनी बहनें तथा मातृशक्ति एकत्रित हुई , जहां पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम हुआ । कार्यक्रम में सरिता व्यास ने अध्यक्षता की , बबिता बेनिवाल , अनिता , लता पांडे दुर्गा वाहिनी क्षेत्रीय संयोजिका ने उद्बोधन में कहा कि विश्व हिन्दू परिषद हिंदुओं की चिंता करने वाला संगठन है । नारी पौराणिक काल से सशक्त रही है , शक्ति स्वरुपा है , नारी नारायणी है , अपनी क्षमताओं को पहचाने , देश के गद्धारो का संहार करना है ।

नवरात्र का पर्व शक्ति का पर्व है । नवरतन पंवार, ओमप्रकाश सोनी, गिरधारी बोराना, श्यामसुंदर दाधीच, श्यामसुंदर पाराशर,भगवती लाल टेलर, माया सांखला,पंकज दिवाकर, चन्द्रप्रकाश धनराज गजानंद , कोमल,श्वेता,जयश्री सोनी, मुनी, सरस्वती, सहित मातृशक्ति, गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे ।

मुस्लिम परिवार बना रहा रावण का पुतला, 51 फीट होगी ऊंचाई

आवाज़ ए तसनीम



सोनभद्र। दुर्गोत्सव का उत्साह चरम पर है तो दशहरा की तैयारी भी शुरू हो गई है। असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में लंकेश रावण का पुतला जलाया जाना है। जिले में अलग-अलग स्थानों पर रावण दहन के लिए पुतला बनाया जा रहा है, मगर इसमें भी दुद्धी में तैयार हो रहा पुतले से जुड़ी कहानी रोचक है। यह पुतला एक मुस्लिम परिवार तैयार कर रहा है। जौनपुर से आए इस परिवार को 51 फीट ऊंचे पुतला बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे वह पूरे मनोयोग से निभाने में लगे हैं। कारीगर एखलाक के मुताबिक 35 वर्ष पहले वह इस कार्य से जुड़े थे और आज भी परंपरा का उसी शिद्दत से निर्वहन कर रहे हैं। जौनपुर जिले के केराकत निवासी एखलाक अपनी पत्नी रानी और बेटे हसरत के साथ मिलकर हर साल रावण का पुतला तैयार करते हैं। रामलीला कमेटी का भरोसा और परिवार की पुश्तैनी कला दोनों ने इस काम को दुद्धी की रामलीला का अभिन्न हिस्सा बना दिया है। दुद्धी रामलीला कमेटी इस वर्ष 51 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनवा रही है। इसके निर्माण का जिम्मा एखलाक को 65 हजार रुपये में सौंपा गया है। कमेटी अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रहरि और महामंत्री सुरेंद्र गुप्ता के मुताबिक कई वर्षों से पुतला निर्माण का काम इसी परिवार से कराया जा रहा है। उनके बीच बना सहयोग और विश्वास गंगा-जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे की मिसाल है। एखलाक बताते हैं कि पुतला बनाना उनके परिवार का पुश्तैनी व्यवसाय है और इसी से घर की आजीविका चलती है। दुद्धी के अलावा वह प्रयागराज की इको कंपनी के लिए भी रावण का पुतला बनाते हैं। वहां इस काम के लिए उन्हें 70 हजार रुपये मिल रहे हैं। रावण दहन के आयोजन में उनके परिवार की कला भले ही कुछ देर बाद अग्नि के हवाले हो जाए, लेकिन उससे जुड़ी मेहनत और परंपरा हर साल लोगों के सामने आती है।

मुस्लिम धर्म अपनाने वालों को आरक्षण न मिलने से हज़ारों परिवारों पर क्या असर पड़ेगा?

आवाज़ ए तसनीम



सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्तूबर को मद्रास हाई कोर्ट के उस फ़ैसले को बरक़रार रखा, जिसमें कहा गया था कि हिंदू रहते हुए पिछड़े वर्ग के तहत मिले हुए आरक्षण का लाभ किसी को इस्लाम धर्म अपनाने के बाद नहीं मिल सकता.

मनिथानेया मक्कल काची (एमएमके) के नेता जवाहिरुल्लाह ने बीबीसी तमिल को बताया कि इस फ़ैसले से इस्लाम अपनाने वाले लोगों के बच्चों को शिक्षा और रोज़गार में आरक्षण का लाभ लेने में मुश्किलें आएंगी और हज़ारों परिवार प्रभावित होंगे.

वहीं, तमिलनाडु के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री शाहजहाँ ने कहा है कि राज्य सरकार इस्लाम अपनाने वाले लोगों को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है.

राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पुनर्विचार याचिका दायर करने समेत क़ानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फ़ैसले को बरक़रार रखा, जिसमें तमिलनाडु सरकार के 2024 के आदेश को रद्द कर दिया गया था. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक़, जजों ने कहा, 'सिर्फ़ इस्लाम अपनाने से कोई व्यक्ति राज्य के सात मुस्लिम पिछड़े वर्गों में से किसी एक का सदस्य नहीं बन सकता. उसकी पिछली जातिगत पहचान को मुस्लिम पिछड़े वर्ग की पहचान में नहीं बदला जा सकता. इसी तरह, सिर्फ़ धार्मिक पहचान के आधार पर भी यह तय नहीं किया जा सकता कि वह आरक्षण का हक़दार है या नहीं. 'अदालत ने यह भी कहा कि संविधान के मुताबिक़, हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक़, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ तमिलनाडु सरकार की अपील ख़ारिज कर दी.

बीकानेर में कौमी एकता की मिसाल, मुस्लिम कलाकार मोहसिन खान 19 वर्षों से बन रहे श्रीराम



आवाज़ ए तसनीम

बीकानेर में मुस्लिम कलाकार मोहसिन खान पिछले 19 वर्षों से रामलीला में भगवान श्रीराम की भूमिका निभा रहे हैं। वह नेताजी सुभाष कला मंडल की रामलीला का निर्देशन भी करते हैं। इस आयोजन में विभिन्न धर्मों के 80 से अधिक कलाकार और सहयोगी बिना पारिश्रमिक के भाग लेते हैं।

मुस्लिम कलाकार मोहसिन खान पिछले 19 वर्षों से रामलीला के मंच पर भगवान श्रीराम का किरदार निभाकर आपसी सौहार्द और कौमी एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं। वह नेताजी सुभाष कला मंडल की रामलीला में अभिनय करने के साथ ही इसका निर्देशन भी कर रहे हैं। नवरात्र के अवसर पर आयोजित इस मंचन के जरिये वह भगवान राम के आदर्शों, मर्यादा, करुणा और त्याग के संदेश को लोगों तक पहुंचा रहे हैं।

कौमी एकता और निस्वार्थ सेवा

नेताजी सुभाष कला मंडल की यह रामलीला केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपसी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव की तस्वीर प्रस्तुत करती है। इस आयोजन में हिंदू और मुस्लिम सहित विभिन्न धर्मों के 80 से अधिक छोटे-बड़े कलाकार और सहयोगी निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं। इस मंचन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सभी कलाकार बिना किसी पारिश्रमिक के अपना योगदान दे रहे हैं। इन सभी का उद्देश्य भगवान राम के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाना और बीकानेर की साझी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखना है।

कला और इंसानियत का संदेश

रामलीला के निर्देशक और कलाकार मोहसिन खान का मानना है कि कला को धर्म और मजहब के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। उनके अनुसार कला का असली उद्देश्य लोगों को आपस में जोड़ना और समाज में इंसानियत का संदेश फैलाना है। वह इंसानियत को ही सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। पिछले 19 वर्षों से इस आयोजन से जुड़े रहने के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं हुई। उनके लिए मंच पर भगवान राम के आदर्शों को प्रस्तुत करना सामाजिक सद्भाव और मानवीय मूल्यों को मजबूत करने का सशक्त माध्यम है।

परंपरा संरक्षण की चुनौतियां

आज की युवा पीढ़ी डिजिटल दुनिया और मोबाइल में अधिक व्यस्त होती जा रही है। इसके चलते पारंपरिक आयोजनों में दर्शकों की भागीदारी बनाए रखना और रामलीला के मंचन के लिए आर्थिक संसाधन जुटाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसके बावजूद, सभी कलाकार अपनी सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने में निरंतर लगे हुए हैं। उनका प्रयास है कि आने वाली पीढ़ियां भी भारतीय संस्कृति, धार्मिक कथाओं और सामाजिक एकता के महत्व को समझें। बीकानेर की यह रामलीला दर्शाती है कि जब उद्देश्य इन्सानियत और प्रेम का संदेश देना हो, तो धर्म की दीवारें अपने आप छोटी पड़ जाती हैं।

रामलीला के मंच से भाईचारे का संदेश, हिंदू-मुस्लिम मिलकर सहेज रहे साझी विरासत

आवाज़ ए तसनीम



कुशीनगर। मठिया माधोपुर की रामलीला करीब दो शताब्दियों से सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल पेश कर रही है। यहां रामलीला के आयोजन में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग मिलकर भागीदारी करते हैं। मुस्लिम कलाकार रावण का पुतला तैयार करने में सहयोग करते हैं तो राम-सीता विवाह के आयोजन में हल्दी भेजकर न्योता देने की परंपरा भी निभाई जाती है।

माधोपुर की रामलीला की खासियत केवल इसके ऐतिहासिक मंचन और कलाकारों की उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। करीब दो शताब्दियों से चली आ रही यह परंपरा धर्म और जाति से ऊपर उठकर आपसी भाईचारे का संदेश दे रही है। आयोजन में अलग-अलग समुदायों की भागीदारी इसे विशिष्ट बनाती है। रावण के पुतले को तैयार करने के लिए बांसफोड़ समाज के लोग बत्तियां बनाते हैं, जबकि मुस्लिम कलाकार पुतले को आकार देने में सहयोग करते हैं।

इस तरह रामलीला की तैयारियों में विभिन्न समुदायों के लोग अपनी भूमिका निभाते हैं। राम-सीता विवाह के आयोजन में भी आपसी मेल-जोल की यह परंपरा दिखाई देती है। भारतीय संस्कृति और लोक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हल्दी भेजकर लोगों को विवाह का न्योता देने की रस्म निभाई जाती है। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी रहती है। मठिया माधोपुर की रामलीला इस बात की मिसाल है कि लोक परंपराएं लोगों को जोड़ने का काम करती हैं।

गांव के सब्बल अंसारी, इशू अंसारी, हमीद अंसारी रावण का पुतला बनाते हैं जबकि विभांशु वैभव मिश्र राम, विकास दुबे, माता सीता का पात्र निभाते हैं। इस परंपरा को संजोने में युवाओं की महती भूमिका है। पीढ़ियों से चली आ रही इस परंपरा में धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक सद्भाव भी रचा-बसा है। यही वजह है कि यहां की रामलीला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि गंगा-जमुनी तहजीब और साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी बनी हुई है। नवरात्र में गांव का उल्लास देखने लायक रहता है। लोग जाति-धर्म की परवाह किए बगैर साथ में त्योहार मनाते हैं। होश संभालने के बाद से रामलीला में सहयोग कर रहा हूं और रावण का पुतला बनाने का कार्य करता हूं। मेरे पूर्वज भी यही काम करते थे।

समर मुस्लिम फंड उठाएगा अनाथ बच्चों की पढ़ाई का पूरा

अध्यक्ष अकबर सैफी का ऐलान, हिंदू-मुस्लिम सभी को मिलेगा लाभ

आवाज़ ए तसनीम



गोहावर(नूरपुर) बिजनौर बिजनौर जिले के नूरपुर ब्लॉक के गोहावर से एक खबर सामने आई है। समर मुस्लिम फंड गोहावर ने एक फैसला लिया है कि वह अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगा।

फंड के अध्यक्ष अकबर सैफी ने ऐलान किया है कि गोहावर क्षेत्र के ऐसे सभी अनाथ बच्चे, जिनके माता-पिता दोनों नहीं हैं, उनकी पूरी स्कूल फीस फंड द्वारा दी जाएगी।

यह मदद बिना किसी धर्म या जाति के भेदभाव के दी जाएगी। अकबर सैफी ने साफ किया कि बच्चा हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी धर्म का हो, अगर वह पढ़ना चाहता है तो उसकी शिक्षा का खर्च फंड उठाएगा।

फीस का भुगतान सीधे बच्चे के हाथ में न देकर, स्कूल में किया जाएगा। जरूरतमंद बच्चे या उनके माता-पिता समर मुस्लिम फंड गोहावर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल

जयपुर में मुस्लिम कलाकार तैयार कर रहे रावण का पुतला, 105 फीट ऊंचाई

आवाज़ ए तसनीम



नवरात्रि के मौके पर जयपुर में आपसी एकता-भाईचारे, सद्भावना और सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश की जा रही है. जयपुर शहर में दशहरे के सबसे बड़े आयोजन में 105 फीट ऊंचाई के जिस पुतले का दहन किया जाएगा, उसे मुस्लिम समुदाय के 20 कलाकार तैयार कर रहे हैं. मुस्लिम कलाकारों की यह टीम दो महीने पहले ही मथुरा से जयपुर आ गई थी. जयपुर की दशहरा कमेटी विजयादशमी के दिन इन कलाकारों को मंच से सम्मानित कर अनूठा संदेश देने का भी काम करेगी.

जयपुर शहर की दशहरा कमेटी के रावण के पुतले को तैयार करने का काम मथुरा के मुस्लिम कलाकारों की टीम पिछली पांच पीढ़ियों से कर रही है. यहां रावण के पुतले को तैयार करने का काम जन्माष्टमी के अगले दिन से ही शुरू हो जाता है. मथुरा के मुस्लिम समुदाय के चांद बाबू अपने परिवार और सहयोगियों के साथ अगस्त के पहले हफ्ते में ही यहां आ गए थे. यह मुस्लिम कलाकार डेढ़ दो महीने तक यहां पूरे नियम और संयम का पालन करते हुए राम मंदिर में ही रहते हैं.

चांद बाबू के पूर्वजों ने तैयार किया था रावण का पुतला बनाने का काम

यहां रावण का पुतला तैयार करने वाले कलाकार अलग- अलग दूसरे कामों से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां के पुतले को तैयार करने का काम यह अपने पूर्वजों की परंपरा को निभाने के लिए करते हैं. पांच पीढ़ी पहले चांद बाबू के पूर्वजों ने सबसे पहले यहां पुतला तैयार किया था. 65 साल पहले 20 फीट का पुतला महज़ ढाई सौ रूपये में तैयार हुआ था.

'कलाकारों को धर्म के नजरिये नहीं देखना चाहिए'

आदर्श नगर कमेटी के उपाध्यक्ष राजीव मनचंदा के मुताबिक कलाकार तो सिर्फ कलाकार ही होते हैं. उन्हें हिंदू मुस्लिम के नजरिए से कतई नहीं देखा जा सकता. इनका कहना है कि उनके यहां रावण का पुतला बनाने वाले कलाकार जिस समर्पण भाव से काम करते हैं, वह बेमिसाल है. यही वजह है कि कमेटी उनके काम का सम्मान करती है.

जयपुर के आदर्श नगर में होता है सबसे बड़ा आयोजन

जयपुर शहर में दशहरे का सबसे बड़ा आयोजन आदर्श नगर में ही होता है. यहां रावण के 105 फीट ऊंचे पुतले का दहन किया जाता है. पुतला दहन से पहले जमकर आतिशबाजी की जाती है. इस कार्यक्रम को देखने के लिए तकरीबन एक लाख लोग जुटते हैं.

'काम से हटने के बाद भी निभा रहे हैं पूर्वजों की रस्म'

पुतला बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों का कहना है कि तीन पीढ़ी पहले ही इस काम से हटने के बाद भी वह अपने पूर्वजों की रस्म को निभा रहे हैं. यहां उन्हें जो सम्मान मिलता है, वह लाखों रुपए से बढ़कर है. मुख्य कारीगर चांद बाबू के छोटे भाई को 15 साल पहले 2011 में यहां पुतला बनाने के दौरान पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी. परिवार का मानना है कि प्रभु राम की कृपा की वजह से ही उन्हें बेटा हुआ था.

ठहराए जाते हैं मुस्लिम कलाकार

जयपुर का दशहरा आयोजन हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब की अनूठी मिसाल पेश करता है. मथुरा से आने वाले मुस्लिम कलाकारों को प्रभु राम के मंदिर में ठहराया जाता है और यही उनके रहने खाने की व्यवस्था भी की जाती है. कमेटी उपाध्यक्ष राजीव मनचंदा का कहना है कि वह देश के सामने एक अनूठी मिसाल पेश कर अलग संदेश देना चाहते हैं.

मुस्लिम कारीगर बना रहे 60 फीट ऊंचा रावण, परिवार की चौथी पीढ़ी जुड़ी



आवाज़ ए तसनीम

औरैया। औरैया में दशहरा पर्व को लेकर शहर में तैयारियां तेज हो गई हैं। तिलक नगर स्थित रामलीला मैदान में रावण दहन के लिए करीब 60 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है। इसकी खास बात यह है कि पुतले का निर्माण मुस्लिम कारीगर कर रहे हैं। यह परंपरा हिंदू-मुस्लिम एकता और आपसी सौहार्द का संदेश दे रही है।

जालौन जिले के मुस्लिम कारीगर कई दशकों से रावण के पुतले बनाने का काम कर रहे हैं। कारीगर अफसर के मुताबिक, उनके परिवार की चौथी पीढ़ी इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। दशहरा जैसे पर्व पर पुतला निर्माण में जुटे कारीगरों का योगदान भारतीय संस्कृति की साझा विरासत को दर्शाता है। यह पहल गंगा-जमुनी तहजीब और सामाजिक सद्भाव की मिसाल पेश करती है।

कोलकाता भगदड़ पर जमाअत इस्लामी हिंद ने जताया दुख, पारदर्शी जांच की मांग

आवाज़ ए तसनीम

नई दिल्ली। जमाअत इस्लामी हिंद ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। संगठन ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जमाअत ने घटना की उच्चस्तरीय और पारदर्शी जांच कराने, जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।

जमाअत इस्लामी हिंद के नायब अमीर प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने 18 अक्टूबर को जारी बयान में कहा कि कोलकाता में भगदड़ के कारण हुई जनहानि से संगठन को गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक आयोजनों में निर्दोष लोगों की जान जाना बेहद चिंताजनक है। इस हादसे के कारणों और परिस्थितियों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, ताकि वास्तविक तथ्यों का पता लगाया जा सके।

उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग

प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने कहा कि प्रशासन को हादसे की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए उच्चस्तरीय और पारदर्शी जांच करानी चाहिए। जांच केवल सरकारी रिपोर्ट तैयार करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसके निष्कर्षों के आधार पर ठोस सुरक्षा उपाय भी लागू किए जाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक आयोजनों में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए और यदि जांच में किसी की लापरवाही सामने आती है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर जोर

जमाअत के नायब अमीर ने कहा कि यह हादसा सार्वजनिक आयोजनों में सुरक्षित योजना और बेहतर भीड़ प्रबंधन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। त्योहारों, धार्मिक आयोजनों और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होना बेहद जरूरी है।

उन्होंने कहा कि क्षमता से अधिक भीड़, खराब मौसम, अफरातफरी और कमजोर सुरक्षा व्यवस्था किसी आयोजन को बड़े हादसे में बदल सकती है। ऐसे आयोजनों में पुलिस, प्रशासन और आयोजकों के बीच प्रभावी समन्वय होना चाहिए।



प्रोफेसर सलीम इंजीनियर के अनुसार, आयोजकों और अधिकारियों को संभावित खतरों का पहले से आकलन करना चाहिए। लोगों के आने-जाने के लिए सुरक्षित रास्ते बनाए जाने चाहिए, भीड़ की आवाजाही नियंत्रित की जानी चाहिए और जरूरत के अनुसार पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होनी चाहिए। आपात स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा सहायता और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं भी पहले से तैयार रहनी चाहिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में आम लोगों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग

प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने हादसे से प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि घायलों को उचित चिकित्सा सुविधा दी जानी चाहिए और मृतकों के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।

जमाअत इस्लामी हिंद ने पश्चिम बंगाल सरकार और संबंधित अधिकारियों से निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने, भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा त्योहारों के दौरान लोगों की जान बचाने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की है। संगठन ने कहा कि ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए समय रहते योजना बनाना, प्रशासनिक जवाबदेही तय करना और मानव जीवन की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना आवश्यक है।

ایک انتباہ: تلنگانہ اور اس سے آگے ایل نینو (El Niño) کا سایہ

- تلنگانہ میں پانی کے ممکنہ بحران کے پیشِ نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت۔
- ایل نینو کے اثرات سے بارشوں میں کمی کا خدشہ، آبی وسائل کے تحفظ پر زور۔
- حیدرآباد سمیت شہری علاقوں میں پانی کی بڑھتی قلت، ہر قطرے کے محتاط استعمال کی اپیل۔
- پینے کے پانی کو ترجیح دینے کی ضرورت، کسانوں اور عوام سے تعاون کی اپیل۔
- **پانی، بجلی اور گھریلو اخراجات میں کفایت شعاری سے ممکنہ مشکلات کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔**



آوازِ تسنیم

اربن تلنگانہ کو پانی کے طویل بحران کا سامنا : حیدرآباد کے شہری علاقوں اور پورے تلنگانہ کے قصبوں کو پانی کے ایک ایسے طویل بحران کا سامنا ہے جو 2027 کے وسط تک جاری رہ سکتا ہے۔ اکتوبر کی معمول کی سطح تقریباً 460 ٹی ایم سی (TMC) کے مقابلے میں آبی ذخائر اس وقت تقریباً 200 سے 209 ٹی ایم سی پر ہیں۔ کرشنا طاس میں پانی کا ذخیرہ پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 72 فیصد کم ہے، جبکہ گوداور طاس میں 40 سے 42 فیصد کمی واقع ہوئی ہے۔ 23 سے 28 فیصد تک بارش کے خسارے کی وجہ سے زیرِ زمین پانی کی سطح تیزی سے گر رہی ہے۔ بہت سے علاقوں میں، خاص طور پر آئی ٹی کوریڈورز اور پھیلتے ہوئے رہائشی حصوں میں، بورویلز خشک ہو رہے ہیں۔ واٹر ٹینکرز کی طلب پہلے ہی گرمیوں کی سطح پر پہنچ چکی ہے- روزانہ بکنگ 5,000 سے 8,000 کے درمیان ہے، جو معمول کے آف سیزن کے مقابلے میں دگنے سے بھی زیادہ ہے- اور حالیہ ہفتوں میں پانی کی مجموعی طلب میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ اگر پانی کی بچت نہ کی گئی تو مستقبل میں فراہمی کے شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

ایک سپر ایل نینو دنیا بھر کے موسم کی تشکیل نو کر رہا ہے: یہ کوئی معمولی خشک سالی نہیں ہے۔ یہ ایک مضبوط ہوتے ہوئے ''سپر'' ایل نینو کا مقامی روپ ہے' جو استوائی پیسیفک (equatorial Pacific) کا ایک غیر معمولی گرم ہونا ہے، جو پہلے ہی پوری دنیا میں درجہ حرارت اور بارش کے پیٹرن کو بدل رہا ہے۔ تخمینے بتاتے ہیں کہ 2026 کے آخر تک اہم NiNo-3.4 خطے میں سمندر کی سطح کے درجہ حرارت کی بے ضابطگیاں (anomalies) 3.7+ ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر سکتی ہیں، جو 16-2015 کے عروج سے بھی زیادہ مضبوط ہوں گی، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ شدید سے انتہائی شدید حالات 2027 کے اوائل تک برقرار رہیں گے۔ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن (WMO) نے تقریباً 100 ممالک میں اس کے اثرات سے خبردار کیا ہے۔ یہ پیٹرن شدید گرمی، مون سون کے تعطل، بعض علاقوں میں خشک سالی اور دیگر میں سیلاب، غذائی نظام پر دباؤ، اور صحت و توانائی کی فراہمی کو لاحق خطرات سے جڑا ہوا ہے۔ خود بھارت میں جنوب مغربی مونسون طویل مدتی اوسط سے تقریباً 12.6 فیصد کم ریکارڈ کیا گیا- جو کہ 11 سالوں میں سب سے کمزور ہے۔ جس کی وجہ سے ملک کے بڑے حصے پانی کی قلت کا شکار ہیں۔

دیگر ریاستیں بھی گرمی محسوس کر رہی ہیں اور قیمتیں بڑھ رہی ہیں: مہاراشٹر، کرناٹک، آندھرا پردیش اور راجستھان اور مدھیہ پردیش کے کچھ حصوں میں پہلے ہی خشک سالی کا اعلان کیا جا چکا ہے یا شدید زرعی دباؤ دیکھا جا رہا ہے۔ گنے کی فصلیں، جو گھریلو چینی اور ایتھنول دونوں کے مقاصد کے لیے اہم ہیں، ناکافی بارشوں اور گرمی کی وجہ سے متاثر ہوئی ہیں۔ پیداوار کے تخمینے میں نمایاں کٹوتیاں کی گئی ہیں، قیمتیں بڑھ چکی ہیں، اور بھارت' جو عام طور پر برآمد کنندہ ہے' نے درآمدات کے لیے دروازے کھول دیے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خوراک کی مہنگائی پر اوپر کی طرف دباؤ پڑ رہا ہے ایسے وقت میں جب گھرانے اس کا بوجھ اٹھانے کی سب سے کم استطاعت رکھتے ہیں۔ خوراک، چارے، بجلی اور نقل و حمل کے زیادہ اخراجات مجموعی مہنگائی کو مزید اوپر دھکیل سکتے ہیں بالکل اسی وقت جب معیشت اس صدمے کو جذب کر رہی ہے۔

وزیرِ اعلیٰ کی اپیل: پینے کے پانی کو ترجیح دیں: تلنگانہ کے وزیرِ اعلیٰ اے ریونت ریڈی نے اس صورتحال کو غیر معمولی حد تک واضح انداز میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے آنے والے آٹھ سے دس مہینوں کو انتہائی مشکل قرار دیا ہے- جو کہ خلل کی شدت کے لحاظ سے کووڈ کے دور کے برابر ہے اور کسانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پانی کی زیادہ کھپت والی ربیع (یاسانگی) دھان کی کاشت کو موخر کریں تاکہ نایاب ذخائر کو تقریباً 24,000 دیہاتوں کے لیے پینے کے پانی کو ترجیح دی جا سکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ''کچھ بھی خریدا جا سکتا ہے، لیکن پانی نہیں خریدا جا سکتا''، انہوں نے ہر قطرے کو بچانے اور بجلی کے محدود استعمال پر زور دیا ہے کیونکہ بجلی کی طلب پہلے ہی 20,000 میگاواٹ سے تجاوز کر چکی ہے۔

حکومت ہنگامی اقدامات کی تیاری کر رہی ہے اور مرکزی تعاون کی خواہاں ہے، لیکن دیرپا ریلیف کا دارومدار عوامی تعاون پر ہے۔

شہریوں کو پانی، بجلی اور رقم کا دانشمندانہ استعمال کرنا چاہیے: شہری گھرانے جو کبھی میونسپل سپلائی اور ٹینکرز کو قابلِ اعتماد بیک اپ سمجھتے تھے، اب اس حقیقت کا سامنا کر رہے ہیں کہ زیرِ زمین پانی محدود ہے اور آبی ذخائر دوبارہ نہیں بھر رہے ہیں۔ عام نظم و ضبط' چھوٹے شاورز لینا، پینے کے پانی سے کار نہ دھونا، لیک ہونے والی چیزوں کی فوری مرمت کرنا، پودوں کے لیے گرے واٹر (استعمال شدہ پانی) اکٹھا کرنا، واشنگ مشین اور ڈش واشر کو صرف اس وقت چلانا جب وہ بھرے ہوں- لاکھوں کی آبادی والے شہر میں تیزی سے اثر دکھاتا ہے۔

یہی اصول بجلی پر بھی لاگو ہوتا ہے: کولنگ اور پمپنگ کی وجہ سے بجلی کی چوٹی کی طلب (peak demand) گرڈ پر دباؤ ڈالتی ہے اور ہر ایک کے لیے اخراجات بڑھاتی ہے۔ دانشمندانہ خرچ بھی اہم ہے۔ خوراک اور ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے، لہذا جو گھرانے وسائل کی بچت کریں گے اور اسراف سے بچیں گے وہ آنے والے مہینوں کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکیں گے۔

یہ کوئی گھبراہٹ پھیلانا نہیں ہے' یہ تیاری ہے۔ ایل نینو بھارت یا تلنگانہ کو کسی بھی دوسرے خطے کی طرح معاف نہیں کرے گا۔ مشکلات اور قابو میں آنے والی قلت کے درمیان کا فرق شہروں، قصبوں اور دیہاتوں کی اجتماعی ضبطِ نفس سے ناپا جائے گا۔ آج پانی اور بجلی کی بچت کرنا پینے کے پانی کی فراہمی، جہاں تک ممکن ہو کھڑی فصلوں، اور گھریلو بجٹ کی حفاظت کا سب سے عملی طریقہ ہے جب تک کہ اگلا قابلِ اعتماد مانسون- امید ہے کہ جولائی 2027 تک- نہیں آ جاتا۔ وزیرِ اعلیٰ نے اپیل کر دی ہے۔ اب یہ شہریوں کا فرض ہے کہ وہ اس کا جواب دیں۔

•••☆☆☆•••

یہ لاش کس کی ہے؟

- سفید راشن کارڈ بنائیے اپنے پیاروں کو لاوارث نہ چھوڑیئے۔
- مرکزی ہیلتھ اسکیم سے فائدہ اٹھائیے۔
- صحت ہی زندگی ہے، ہیلتھ انشورنس معاون ہوگا۔

یہ لاش کس کی ہے؟ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں' آخر یہ کس کی ہیں؟ جی ہاں یہ لاشیں لاوارث ہیں۔ کسی رشتہ دار نے اپنے پیارے کو ہاسپٹل میں شریک کیا اور فرار ہو گیا۔ کوئی غربت سے مارا گیا، کوئی تنگ دستی سے ختم ہو گیا۔ ان کے وارث تو ضرور ہوں گے لیکن انہیں لاوارث چھوڑ کر جانے میں ہی اپنی خیریت سمجھی۔ کئی لوگ ہیلتھ انشورنس نہ ہونے کے سبب موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہاسپٹل کے سفاک قاتل اتنے تجارت پیشہ ہو گئے ہیں کہ وہ زندگی کے فلسفہ کو بھول گئے ہیں اور مریض کو ہر طرح سے تنگ کرتے ہوئے اسے مرنے سے پہلے ہی مار ڈالتے ہیں۔ حالات حاضرہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے بیشتر علماء دین نے سفارش کی ہے کہ ہیلتھ انشورنس لیا جاسکتا ہے تاکہ مصیبت کے وقت اس سہولت سے استفادہ کیا جاسکے۔



یہ سوچ بے انتہا اچھی ہی سمجھی جائے گی کہ ہمارے ذمہ دار لوگ مسئلہ کی سنگین نوعیت کو سمجھنے لگے ہیں۔ ہر معاملے میں تنگ نظری کسی بھی حالت میں صحیح نہیں قرار دی جاسکتی۔ اگر ہر مسلمان اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق میڈیکل انشورنس لیتا ہے تو اسے اپنی جائیدادیں یا گھر بیچنے کی نوبت نہیں آتی۔ ہمارے محلہ کا ایک نوجوان جس کی چکن کی دکان ہے اپنی ماں کے علاج کے لئے اپنا گھر رہن رکھ دیا اور ماں کا کامیاب علاج کروا کر اسے گھر لے آیا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس نے ریاستی حکومت کا سفید راشن کارڈ نہیں بنوایا جس کی وجہ سے اسے اپنا گھر رہن رکھنا پڑا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ قرض کی ادائیگی کے لئے اب اپنا گھر بیچ رہا ہے، کیا ملت اس نوجوان کی اس حالت کو بہتر کرنے کے لئے ذمہ دار نہیں ہے۔ یعنی ہمارے این جی اوز آگے بڑھیں اور اس طرح کے مستحق لوگوں کی رہنمائی کریں تاکہ وہ سرکاری رعایتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ایک ذاتی گھر رکھنے والا جب بے گھر ہو جاتا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے وہی جانتا ہے لیکن ماں کی محبت اور اس کی ممتا کی قدر کرنے والے لوگ مال تو کیا اپنی ساری کمائی اس پر نچھاور کر کے بے انتہا مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ایک شاعر نے ایسے ہی لوگوں کے لئے کیا خوب کہا ہے کہ

تیرے قدموں پہ جھکا دوں میں گناہگار جبیں
ہو اجازت تو تجھے آج میں سجدہ کر لوں
تجھ سے کچھ لوں تو فقط تیری دعائیں لے لوں
تجھ کو کچھ دوں تو میری جان کا تحفہ دے دوں

مرکزی حکومت کی جانب سے بھی 70 سال سے تجاوز کرنے والے ہر شخص کے لئے ایک اسکیم نکالی گئی ہے جس میں پانچ لاکھ روپئے تک کا علاج کسی بھی کارپوریٹ ہاسپٹل میں مفت ہو سکتا ہے۔ یہ بہت ہی آسان انشورنس ہے اس کی ساری تفصیلات انٹرنٹ پر موجود ہیں۔ ہمارے این جی اوز اس طرح کی سہولتوں کو عام کرنے کی کوشش کریں تو یہ بہت بڑی خدمت کہلائے گی۔ ہندوستان کے ہیومن رائٹس کمیشن نے تمام ہاسپٹلس کو یہ ہدایت دی ہے کہ بل کی ادائیگی کے لئے کسی بھی شخص کی لاش کو اپنے قبضہ میں نہ رکھیں۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ ہر شخص کو باعزت تدفین یا کریا کرم کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ اگر اس حقیقت کو بھی ہماری تنظیمیں عام کرتے ہیں تو اس لاش کے وارث ایک باعزت ڈھنگ سے اس کی آخری رسومات ادا کر سکتے ہیں۔ ہندوستان میں کارپوریٹ دواخانوں پر سخت نظر رکھی جانی چاہئے تاکہ یہاں پر غریبوں کا علاج انتہائی کم نرخوں پر کیا جاسکے۔ اس سلسلہ میں قانون سازی کی جانی چاہئے۔

دکن کے عظیم حکمران حضور نظام نے جس خوبصورتی کے ساتھ سرکاری دواخانوں میں مفت علاج کی سہولتیں باہم پہنچائی تھیں اس کی تقلید اگر ہماری ریاستی اور مرکزی حکومتیں کرنے لگیں تو ایک سنہرے دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ صحت آج بھوک سے زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ کھانے پر اتنے پیسے نہیں خرچ ہو رہے ہیں جتنے کہ دوائیوں پر۔ دوائیوں کے دام گھٹانے پر بھی حکومت کو توجہ دینی چاہئے، حکومت دعوی کرتی ہے کہ Generic Medicines انتہائی سستے داموں پر مل رہی ہیں لیکن لوگوں کی اکثریت کا یہ تاثر ہے کہ وہ کارکرد ثابت نہیں ہو رہی ہیں۔ اگر آپ سستے داموں پر بے اثر دوائیں فراہم کر رہے ہیں تو اس کا کیا فائدہ؟ بہت ساری بیماریوں کی جڑ شوگر ہے جس کے سبب قلب، گردے، جگر اور گھٹنوں میں درد کی شکایت عام ہو جاتی ہے۔ آج کل دواخانوں میں سب سے زیادہ مریض دل کی بیماریوں اور کینسر کی وجہ سے شریک ہو رہے ہیں۔ ان امراض کے علاج میں تاخیر کے سبب موت واقع ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کے پاس سفید راشن کارڈ ہے ان کا علاج کارپوریٹ دواخانوں میں بھی مفت میں ہوتا ہے لیکن افسوس ہے کہ لوگ اتنے اہم مسئلہ پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ حیدرآباد شہر میں کینسر کا ایک بہت بڑا مرکز ہے جسے لوگ مہدی نواز جنگ کینسر ہاسپٹل کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں پر کینسر کا علاج انتہائی کامیابی کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن اس بات کا افسوس ہے کہ لوگوں کو اس دواخانہ کی عظمت کا علم نہیں ہے۔ اسی دواخانہ کے بازو معصوم بچوں کے لئے بھی ایک سرکاری دواخانہ ہے جسے ہم سب نیلوفر ہاسپٹل کے نام سے جانتے ہیں جو شیر خواروں کی بہترین خدمت کر رہا ہے۔ اگر ہم ان دواخانوں سے فائدہ اٹھائیں تو نہ صرف لاکھوں روپیوں کی بچت ہوگی بلکہ ہمارے پیاروں کا علاج بھی کامیاب ڈھنگ سے ہو جائے گا۔

•••☆☆☆•••

الیکشن کمیشن کی ساکھ کیسے بحال ہوگی؟

آوازِ تسنیم

طویل عرصے بعد بھارت میں اپوزیشن جماعتوں کو کسی ایک مسئلے پر متحد ہوتے دیکھا گیا ہے۔ 12 اکتوبر کو دہلی میں کانگریس کی قیادت میں اپوزیشن جماعتوں نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو ہٹانے، ایس آئی آر کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ تک مارچ کیا۔ اس کے بعد مارچ میں شامل سینئر اپوزیشن رہنماؤں نے ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں دائر مشترکہ عرضی میں یہ مسائل اٹھائے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف تمام احتجاج صرف ایک ہی احتجاج کا حصہ ہیں۔ یہ بالواسطہ طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کے ایک ملک، ایک انتخاب کے مسئلے کا جواب ہے۔ 2014 کے بعد پہلی بار اپوزیشن کو کسی ایک مسئلے پر پوری طاقت کے ساتھ متحد ہو کر آواز اٹھاتے دیکھا گیا ہے۔

اب تک اپوزیشن جماعتیں ریاستوں میں اپنے مفادات کے مطابق الگ الگ جدوجہد کرتی رہی ہیں۔ انتخابات کے وقت مقامی سطح پر اتحاد ہو جاتے ہیں۔ کئی بار پارلیمنٹ میں کچھ مسائل پر اتحاد نظر آتا ہے۔ لیکن اس بار انتخابات میں دھاندلی کے مسئلے نے اپوزیشن رہنماؤں کو اپنے اختلافات، عزائم اور انا سے بالاتر ہو کر ساتھ آنے پر مجبور کیا ہے۔ اپوزیشن کو احساس ہو گیا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کے خلاف مل کر مہم نہیں چلائی گئی تو اس کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے اس نے زمینی جدوجہد اور قانونی لڑائی میں ساتھ رہنے کا تزویراتی فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی ساکھ پر بحران کے درمیان یہ پیش رفت ایک اچھا اشارہ ہے۔



الیکشن کمیشن کروڑوں ووٹروں کا حق چھین رہا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ نے فیصلہ کن مداخلت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے بہار میں ایس آئی آر کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ پورا عمل قانونی نقطہ نظر سے جائز ہے۔ ایس آئی آر قانونی طور پر جائز تو ہے لیکن اس کا طریقہ غلط ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ نہیں دیکھا کہ جو کام ایک دو سال میں ہونا چاہیے وہ انتخابات سے چند ماہ پہلے عجلت میں کیوں کیا جا رہا ہے۔ اب یہ مسائل عوام کے دل و دماغ پر دستک دینے لگے ہیں۔ کانگریس جنتا پارٹی کی مہم بتاتی ہے کہ نوجوانوں کا ایک طبقہ بھی انتخابات میں دھاندلی کے مسئلے پر مشتعل ہے۔ سیاسی جماعتوں نے اسے مزید واضح اور تیز دھار بنا دیا ہے۔

ایس آئی آر میں دھاندلی کے بارے میں ایک اور انکشاف سامنے آیا ہے۔ انتخابی تجزیہ کار پرنوئے رائے نے مئی 2026 کے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے نتائج پر ایس آئی آر کے اثرات کا تجزیہ کیا ہے۔ اس کے مطابق جن 25 حلقوں میں سب سے زیادہ ووٹروں کو فہرست سے نکالا گیا ہے، وہاں ممتا بنرجی کی ترنمول کانگریس کے خلاف ووٹوں کا جھکاؤ 10.5 فیصد رہا ہے۔ جن حلقوں میں سب سے کم ووٹروں کو باہر کیا گیا ہے، وہاں ترنمول کے خلاف صرف 5.3 فیصد ووٹوں کا جھکاؤ رہا۔ گزشتہ انتخابات کے نتائج بتاتے ہیں کہ ترنمول کو خواتین اور مسلم ووٹروں کی اچھی حمایت ملتی رہی ہے۔ ترنمول کو خواتین کے ووٹ بی جے پی سے 13 فیصد زیادہ ملے ہیں۔ بنگال میں مرد اور خواتین ووٹروں کی تعداد تقریباً برابر ہے۔ لیکن ایس آئی آر میں خواتین کے 62 فیصد اور مردوں کے صرف 38 فیصد ووٹ کم ہوئے ہیں۔ ریاست میں گزشتہ انتخابات میں ترنمول کو مسلمانوں کے 75 فیصد اور بی جے پی کو 7-8 فیصد ووٹ ملے ہیں۔ ایس آئی آر میں غیر مسلموں کے مقابلے مسلمانوں کے 52 فیصد ووٹرز زیادہ باہر ہوئے ہیں۔ یہ تجزیہ پورے عمل کو شک کے دائرے میں کھڑا کرتا ہے۔ لگتا ہے، جان بوجھ کر خواتین اور مسلم ووٹروں کو باہر کیا گیا ہے۔

چیف الیکشن کمشنر کے من مانے اقدامات کا انکشاف ان کے دو ساتھی الیکشن کمشنروں کی جانب سے کیے جانے کے بعد، الیکشن کمیشن نے کچھ اصلاحات نافذ کی ہیں۔ ان دو کمشنروں نے ''فارم 6'' (جو نئے ووٹروں کی رجسٹریشن کے لیے استعمال ہوتا ہے) میں شامل ایک اضافی اعلامیے کو غیر قانونی قرار دیا تھا؛ اسے شہریت کی تصدیق کرنے کی ایک ''پچھلے دروازے'' (خفیہ) کوشش کے طور پر دیکھا گیا۔ مزید برآں، ''فارم 7'' — جو ووٹر کا نام ہٹانے کی درخواست دینے یا انتخابی فہرست میں کسی اندراج پر اعتراض کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے — کے ذریعے بڑی تعداد میں ووٹروں کے نام خارج کرنے کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ کئی ریاستوں سے فارم 7 کے غلط استعمال کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جس پر احتجاج بھی ہوا ہے۔ 9 اکتوبر کو، کمیشن نے تسلیم کیا کہ فارم 7 کی بڑی تعداد میں درخواستیں جمع کرائے جانے سے ووٹروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؛ چنانچہ اب کمیشن نے ایک فرد کی جانب سے جمع کرائے جانے والے ایسے فارمز کی تعداد زیادہ سے زیادہ دس تک محدود کر دی ہے۔

''سسٹمیٹک ووٹرز ایجوکیشن اینڈ الیکٹورل پارٹیسپیشن'' (SVEEP) نامی اقدام — یا اسی طرح کے دیگر عمل — کے متعارف ہونے کے بعد، کرناٹک، اتراکھنڈ، تلنگانہ اور اوڈیشہ میں سیاسی جماعتوں نے اپنے حریفوں پر الزام لگایا کہ وہ بڑی تعداد میں فارم 7 کی درخواستیں جمع کروا رہے ہیں۔ ستمبر میں، بیجو جنتا دل (BJD) نے یہ معاملہ اوڈیشہ کے چیف الیکٹورل آفیسر کے سامنے اٹھایا۔ کچھ بوتھ لیول آفیسرز (BLOs) نے تو پولیس میں شکایت بھی درج کرائی، جس میں الزام لگایا گیا کہ ان کی معلومات کے بغیر ان کے نام سے فارم 7 کی درخواستیں جمع کرائی گئی تھیں۔ اس کے جواب میں، الیکشن کمیشن نے ایک عہدیدار کو عہدے سے ہٹا دیا۔

الیکشن کمیشن میں بے ضابطگیوں کی فہرست بظاہر لامتناہی ہے۔ اس پر ''ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ'' (ضابطہ اخلاق) کی خلاف ورزیوں کے معاملے میں جانبداری برتنے — یعنی اپوزیشن کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے حکمران جماعت کی حمایت کرنے — کا الزام لگایا گیا ہے۔ ایسے واقعات 2019 اور 2024 کے لوک سبھا انتخابات، دونوں کے دوران دیکھے گئے۔ گیانیش کمار سے قبل، راجیو کمار — جو اب ملک کے سب سے بڑے نجی شعبے کے بینک، HDFC کے چیئرمین ہیں — بھی اپوزیشن کی تنقید کا نشانہ بنے تھے۔ اپنے دورِ ملازمت میں، ان پر حکمران جماعت کے ساتھ ضرورت سے زیادہ نرم رویہ اختیار کرنے کے الزامات لگے تھے۔

الیکشن کمیشن کے کام کاج میں شفافیت کے فقدان سے متعلق شکایات کی تائید میں کافی شواہد موجود ہیں۔ یہ ادارہ اب اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے کے حوالے سے ایک بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ اگرچہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک خودمختار اور آزاد ادارہ ہے جو کسی بھی بیرونی مداخلت کے بغیر کام کرتا ہے، لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہی کہانی بیان کرتے ہیں۔ اس کے باوجود، حکومت ہمیشہ اپنا دفاع کرنے میں پیش پیش رہتی ہے۔ اس بار، حکومت نے اختلافِ رائے کی آوازوں کو دبانے کے لیے انتہائی سخت رویہ اختیار کیا ہے، جن میں الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ دہلی میں، احتجاج کرنے والے سیاسی کارکنوں، وکلاء اور صحافیوں کو ہر موڑ پر روکا گیا؛ مرکزی حکومت نے دارالحکومت کے نظامِ زندگی کو عملی طور پر مفلوج کر دیا۔ مزید برآں، حکام نے ''جنتر منتر'' جو اقتدار کے مراکز کے انتہائی قریب واقع ہے' کی جگہ احتجاج کے لیے تین نئے مقامات مختص کر دیے ہیں۔ ان میں سے براڈی اور شاہدرہ شہر سے کافی فاصلے پر واقع ہیں، جس کی وجہ سے دہلی کے رہائشیوں کے لیے وہاں پہنچنا مشکل ہے' بیرونِ شہر سے آنے والوں کی تو بات ہی چھوڑیں۔ تاہم، تیسرا مقام، 'رام لیلا میدان'، ایک مناسب انتخاب ہے۔

رام لیلا میدان کی اختلافِ رائے کے اظہار کے مقام کے طور پر ایک طویل تاریخ ہے۔ 1975 میں، یہیں سے جے پرکاش نارائن (جے پی) نے اندرا گاندھی کی حکومت کے خلاف تحریک کا بگل بجایا تھا۔ جے پی کے عوامی جلسے سے ابھرنے والا نعرہ — ''تخت خالی کرو، کہ عوام آتے ہیں'' بے حد مقبول ہوا۔ یہ نعرہ رام دھاری سنگھ 'دنکر' کی نظم 'انقلاب کا جنم' (''جمہوریت کی پیدائش'') سے لیا گیا ہے، جسے 1950 میں بھارت کے پہلے یومِ جمہوریہ کے موقع پر لکھا گیا تھا۔ تاہم، اخباری اطلاعات کے مطابق، رام لیلا میدان کی موجودہ حالت خستہ ہے؛ اکتوبر سے دسمبر تک یہاں مسلسل تقریبات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔

جمہوریت میں، عوامی ناراضی کا اظہار ایک ''سیفٹی والو'' (دباؤ کم کرنے والے آلے) کا کام کر سکتا ہے۔ لیکن، حکومتوں سے یہ توقع رکھنا مشکل ہے کہ وہ حزبِ اختلاف کی آوازوں کے لیے کوئی مؤثر پلیٹ فارم فراہم کریں گی۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس جیسی مغربی جمہوریتوں میں، احتجاج کے لیے مختص مقامات اقتدار کے مراکز کے کافی قریب واقع ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس، ہمارے ملک میں عوامی جذبات کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے' ایک ایسا رجحان جو انتخابی فہرستوں میں بے قاعدگیوں کی وجہ سے مزید سنگین ہو گیا ہے۔ اگر لاکھوں ووٹروں کو اپنی مرضی سے حکومت منتخب کرنے سے عملی طور پر روک دیا جائے، تو اس سے زیادہ سنگین بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہوگی کہ بڑھتے ہوئے شواہد کے باوجود کسی کو بھی جوابدہ نہ ٹھہرایا جائے۔ جمہوریت میں، اپوزیشن کا کردار اس بات کو یقینی بنانے میں فیصلہ کن ہوتا ہے کہ عوامی جذبات ٹھوس نتائج کی شکل اختیار کریں۔ اپوزیشن جماعتوں کے مسلسل دباؤ کے ذریعے ہی عوام کے حقِ رائے دہی کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔

•••☆☆☆•••

संपादकीय

नगा गुटः शांति वार्ता की राह हुई आसान

देश की सबसे पुरानी और जटिल नगा उग्रवादी समस्या का सर्वसम्मत हल निकालने के लिए केंद्र सरकार से एकजुट होकर वार्ता चलाने का नगा गुटों का प्रयास स्वागत योग्य है. ऐसी पहल नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालिम - एनएससीएन : आईएम आइजक-मुइवा और एनएससीएन : खपलांग-गुट की ओर से हुई है. अलग स्वतंत्र संप्रभु 'ग्रेटर नगालिम' गठन की मांग हिंसा की बदौलत करने वाले इन दोनों गुटों से केंद्र की कई वर्षों से बेनतीजा वार्ता चल रही है, जो एक-दूसरे के विरोधी हैं.

इनके अलावा कई अन्य गुट भी हैं, जिसमें से सात गुटों के संयुक्त मंच नगा नेशनल पोलिटिकल ग्रुप (एनएनपीजी) के साथ भी केंद्र का संघर्षविराम चल रहा है. ये सारे गुट नगालैंड-मणिपुर-म्यांमार सीमा के अंदर और सीमा पार से अपनी उग्रवादी गतिविधियां चलाते हैं. लगभग सभी गुटों को नगा-आबादी वाले इलाकों को मिलाकर अलग 'ग्रेटर नगालिम' चाहिए.

इनमें सबसे प्रभावशाली और सबसे मजबूत पुराना दावेदार एनएससीएन (आईएम-गुट) है, जिसके साथ सबसे पहले 1997 में केंद्र की संघर्षविराम सहमति बनी. इस गुट से 29 वर्षों से बेनतीजा वार्ता चल रही है. 2015 में केंद्र के साथ 'फ्रेमवर्क डील' पर टी. मुइवा ने दिल्ली में हस्ताक्षर किए, मगर 'फाइनल डील' अभी तक गतिरोध में अटकी है. एनएससीएन (आईएम) सुप्रीमो टी. मुइवा बीच-बीच में 'संघर्षविराम सहमति' और 'फ्रेमवर्क डील' रद्द करने की धमकी देकर केंद्र पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, मगर वार्ता का ठोस नतीजा नहीं निकला है.एनएससीएन (खपलांग गुट) के साथ 2001



में संघर्षविराम सहमति बनी. लेकिन इस गुट से शांति वार्ता या कोई 'डील' हुई है या नहीं, इसकी पक्की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है. हालिया नगा एका शांतिवार्ता की पहल एनएससीएन - के. (खपलांग) के एंग मेई नेतृत्ववाले गुट की ओर से हुई है, जिसका अड्डा म्यांमार सीमा के अंदर है. इस संगठन के अंदर भी कई गुट हैं मगर सबसे ज्यादा नगा कादर एनएससीएन - (खपलांग) के एंग मेई नेतृत्व के साथ हैं. ये सभी भारत और म्यांमार दोनों की सरकारों से वार्ता चलाने तथा आपसी सहमति से हिंसा की परंपरा को त्यागकर शांति, विकास की एक नई शुरुआत के समर्थक हैं.

शांति वार्ता पटरी पर लाने का प्रयास ऐसे समय में शुरू हुआ है, जब मणिपुर में और खासकर म्यांमार से लगे सीमावर्ती जिलों में नगा-कुकी हिंसा पूरे उफान पर है. जातीय तनाव और आपसी टकराव चरम पर है. हिंसा और शांति दोनों के समर्थक तथा विरोधी संगठनों ने अपने वर्चस्व की लड़ाई में एक-दूसरे को उजाड़ने की मुहिम चला रखी है.

नगालैंड और मणिपुर में हिंसा की नींव नगा-उग्रवाद की रखी हुई है. हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि 'अलग संविधान और अलग झंडे' पर एनएससीएन (मुइवा) शांति समर्थक गुटों का रूख क्या होगा, फिर भी नई उम्मीद जगी है. क्योंकि भारत सरकार से संघर्षविराम समझौत करने वाले एनएसपीजी के सात नगा गुट और अन्य संगठन भी अड़ियल रवैया छोड़ने के पक्ष में हैं, ताकि वार्ता का रास्ता खुला रहे. अगर बात बनती है तो स्वायत्तता और स्वशासन जैसी अन्य अलगाववादी हिंसा से भी नगालैंड, मणिपुर की जनता को राहत मिलेगी.

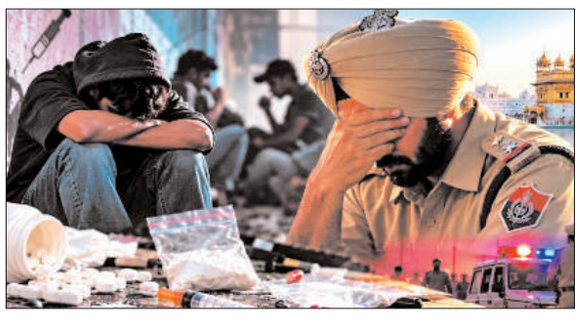
पंजाब में नशे का तांडवः वर्दी बनी त्रासदी

पंजाब की धरती कभी शौर्य, पराक्रम, मेहनत, उद्यमशीलता और जीवटता के लिए जानी जाती थी। इसी मिट्टी के नौजवानों ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और खेतों में पसीना बहाकर देश का अन्न भंडार भरा। लेकिन आज उसी पंजाब की पहचान नशे के बढ़ते कारोबार, युवाओं की बर्बादी और ड्रग्स माफिया के बढ़ते प्रभाव से जुड़ती जा रही है। यह केवल एक राज्य की सामाजिक त्रासदी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, शासन-व्यवस्था और राजनीतिक इच्छाशक्ति की गंभीर परीक्षा है।

ललित गर्ग

जिस पंजाब के युवाओं के हाथों में कभी तलवार, हल और तिरंगा शोभा देते थे, वहां आज नशे ने अनेक हाथों को बेबस और अनेक परिवारों को बदहवास कर दिया है। विडंबना देखिए कि नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी जिन पुलिसकर्मियों की है, यदि उन्हीं के घर से करोड़ों रुपये की हेरोइन बरामद होने की खबर सामने आती है, तो यह व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। पंजाब में एक पुलिस कांस्टेबल के घर से कथित तौर पर 40 करोड़ रुपये की हेरोइन बरामद होने का मामला इसी सड़ांध की ओर संकेत करता है। यह घटना महज एक आपराधिक प्रकरण नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न है, जिसमें अपराध रोकने के लिए नियुक्त व्यक्ति ही कथित तौर पर अपराध के संदेह के घेरे में आ जाए। यह तो वही स्थिति हुई कि 'बाड़ ही खेत को खाने लगे', तो फसल की रखवाली कौन करेगा? जिस पुलिस के कंधों पर नशा तस्करों को पकड़ने का दायित्व है, यदि उसी व्यवस्था के भीतर ऐसे तत्व पनपने लगें, तो आम नागरिक का भरोसा डगमगाना स्वाभाविक है। इस मामले में निष्पक्ष जांच, दोषियों की पहचान और कठोर कानूनी कार्रवाई जरूरी है। किसी व्यक्ति को केवल आरोप के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन वर्दी की आड़ में अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून से बचने का अवसर भी नहीं मिलना चाहिए।

पंजाब में नशे का कारोबार अब गलियों, गांवों और कस्बों तक अपनी जड़ें फैला चुका है। कभी नशे की समस्या को सीमावर्ती क्षेत्रों या शहरी युवाओं तक सीमित माना जाता था, लेकिन आज सिंथेटिक ड्रग्स सहित विभिन्न मादक पदार्थों की उपलब्धता ने संकट को और व्यापक बना दिया है। युवा पीढ़ी का एक हिस्सा नशे की गिरफ्त में आकर अपना स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और भविष्य गंवा रहा है। कहीं मां की गोद सूनी हो रही है, कहीं वृद्ध पिता के बुढ़ापे का सहारा छिन रहा है और कहीं परिवार का कमाऊ सदस्य नशे की लत के कारण स्वयं अपने परिजनों पर बोझ बन रहा है। 'घर का चिराग ही घर में अंधेरा कर दे', इससे बड़ी विडंबना क्या होगी! नशे की लत केवल व्यक्ति को नहीं तोड़ती, बल्कि पूरे परिवार और सामाजिक ताने-बाने को भीतर तक खोखला कर देती है। इस संकट की गंभीरता सरकारी आंकड़ों और पुलिस की कार्रवाइयों से भी समझी जा सकती है। उपलब्ध विवरणों के अनुसार दस महीनों में पंजाब पुलिस ने 10,524 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनमें 153 बड़े ऑपरेटर शामिल थे। इस दौरान 790 किलोग्राम हेरोइन, 860 किलोग्राम अफीम और अन्य मादक पदार्थों के साथ 13 करोड़ रुपये से अधिक की ड्रग मनी जब्त की गई तथा नशे के कारोबार से जुड़ी 208 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति पर कार्रवाई की गई। ये आंकड़े कार्रवाई के पैमाने को अवश्य दर्शाते हैं, लेकिन साथ ही यह सवाल भी उठाते हैं कि इतनी



बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ आखिर राज्य में पहुंच कैसे रहे हैं? इतनी गिरफ्तारियों और जब्ती के बावजूद यदि नशे की उपलब्धता और लत पर निर्णायक अंकुश नहीं लग रहा, तो स्पष्ट है कि समस्या की जड़ें गहरी हैं। 'मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की' जैसी स्थिति से बचने के लिए गिरफ्तारियों की संख्या से आगे बढ़कर नशे की आपूर्ति, वित्तीय नेटवर्क और राजनीतिक संरक्षण की पड़ताल करनी होगी।

पाकिस्तान से लगी पंजाब की लगभग 553 किलोमीटर लंबी सीमा इस चुनौती को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ती है। ड्रोन के माध्यम से नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी की आशंकाएं सीमा प्रबंधन को और जटिल बनाती हैं। वर्ष 2026 में अब तक पंजाब की सीमा से 183 ड्रोन जब्त किए जाने का उल्लेख इस खतरे की गंभीरता को रेखांकित करता है। सीमा पार से संचालित तस्करी के नेटवर्क पर प्रहार करना आवश्यक है, लेकिन सारी जिम्मेदारी बाहरी ताकतों पर डालकर राज्य के भीतर की कमजोरियों से आंखें नहीं मूंदी जा सकतीं। यदि स्थानीय तस्कर, संगठित गिरोह और भ्रष्ट तंत्र मिलकर काम कर रहे हों, तो सीमा पर कड़ी निगरानी के साथ-साथ भीतर भी कठोर कार्रवाई करनी होगी। 'दूध का दूध और पानी का पानी' करने वाली जांच ही बता सकती है कि इस काले कारोबार में कौन मोहरा है, कौन खिलाड़ी और कौन पर्दे के पीछे बैठा सूत्रधार। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने नशामुक्ति और तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर अनेक दावे किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये दावे जमीन पर उतना परिवर्तन ला पाए हैं, जिसकी अपेक्षा पंजाब की जनता ने की थी? सत्ता में आने से पहले नशे के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई के वादे करना आसान है, लेकिन उस लड़ाई को परिणाम तक पहुंचाना राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक ईमानदारी और निरंतर जवाबदेही मांगता है। यदि नशे की उपलब्धता बनी हुई है, युवा लगातार इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं और तस्करी के नेटवर्क बार-बार सक्रिय हो जाते हैं, तो सरकार की रणनीति और उसके क्रियान्वयन पर सवाल उठना स्वाभाविक है। केवल छापेमारी, गिरफ्तारी और घोषणाओं से नशामुक्त पंजाब का सपना साकार नहीं होगा। सरकार की सफलता का वास्तविक पैमाना यह होना चाहिए कि नशे की आपूर्ति कितनी घटी, कितने युवा उपचार के बाद सामान्य जीवन में लौटे और बड़े तस्करों तथा उनके संरक्षकों के विरुद्ध कितनी प्रभावी कार्रवाई हुई।

नशे के खिलाफ लड़ाई में पुलिस सुधार, आधुनिक तकनीक, सीमा सुरक्षा और वित्तीय जांच के साथ-साथ नशामुक्ति केंद्रों, मनोवैज्ञानिक परामर्श, रोजगार और पुनर्वास पर भी समान ध्यान देना होगा। नशे के शिकार युवाओं को केवल अपराधी मानकर खारिज करना समाधान नहीं है, उन्हें उपचार, सहारा और सम्मानजनक जीवन में लौटने का अवसर देना भी जरूरी है। गांवों में जनभागीदारी, स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता और परिवारों की सक्रिय भूमिका इस अभियान को जनांदोलन का स्वरूप दे सकती है।

साप्ताहिक हिन्दी और उर्दू समाचार पत्र

आवाज़ से पहचान तक

आवाज ए تسنیم

HINDI & URDU WEEKLY NEWS PAPER

उम्मीद की एक नई रोशनी

WWW.TASNEEMTV.COM

पॉडकास्ट कार्यक्रम

उम्मीद की एक नई रोशनी

जहाँ इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है।

आवाज़-ए-तसनीम लेकर आ रहा है एक विशेष प्रेरणादायक पॉडकास्ट कार्यक्रम "उम्मीद की एक नई रोशनी", जिसमें हम ऐसे लोगों की सच्ची कहानियाँ आपके सामने लाएँगे जिन्होंने धर्म, मज़हब, जाति और हर तरह के भेदभाव से ऊपर उठकर इंसानियत की मिसाल कायम की है।

यह मंच उन अनसुने नायकों की आवाज़ बनेगा जिन्होंने अपने निस्वार्थ कार्यों से समाज में प्रेम, भाईचारा, सद्भाव और उम्मीद की नई रोशनी जगाई है।

हर प्रेरणादायक कहानी, समाज के लिए एक नई रोशनी।

इस पॉडकास्ट में आप देखेंगे

प्रेरणादायक और अनसुनी जीवन यात्राएँ

मानव सेवा और समाज परिवर्तन की कहानियाँ

सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की मिसालें

विशेष अतिथियों के साथ प्रेरक बातचीत

समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले लोगों की दास्तान

क्या आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है?

क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने धर्म और मज़हब से ऊपर उठकर इंसानियत की मिसाल कायम की हो?

क्या आपके आसपास कोई ऐसा शख्स है जिसने अपने कार्यों से समाज में उम्मीद की नई रोशनी जगाई हो और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया हो?

अगर आपके पास भी ऐसी प्रेरणादायक कहानी है, तो हमसे संपर्क करें।

हो सकता है आपकी बताई हुई कहानी "उम्मीद की एक नई रोशनी" के अगले एपिसोड का हिस्सा बने और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए।

आवाज़ ए तसनीम हिन्दी और उर्दू समाचार पत्र

राजस्थान के सभी जिलों एवं विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ें

खबर, विज्ञापन एवं संवाददाता बनने के लिए संपर्क करें

02269621949 | 8946840063 | 8209508208

tasneemtv.official@gmail.com

आवाज़-ए-तसनीम पॉडकास्ट

उम्मीद की एक नई रोशनी

जहाँ इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है।

तेज़, सटीक और विश्वसनीय खबरें | आपकी आवाज़, हमारी पहचान | एक मज़बूत मीडिया, एक सशक्त समाज | हर खबर पर हमारी नज़र



मुख्य सचिव ने राजस्थान संपर्क पोर्टल के कॉल सेंटर का किया निरीक्षण

पीएम किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना से जुड़े परिवादों का शीघ्र निस्तारण कर किसानों को राहत पहुंचाएंःमुख्य सचिव



जयपुर(नि.सं.)। आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान और परिवादों के निस्तारण में जवाबदेही सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने रविवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क पोर्टल के कॉल सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने



वीडियो कॉल के माध्यम से परिवादकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सहकारिता, परिवहन, कृषि एवं राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से संबंधित परिवादों की समीक्षा करते हुए उनके निस्तारण की स्थिति जानी। उन्होंने परिवादकों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी ली। इस दौरान बहादुर सिंह एवं राधे जी ने मुख्य सचिव को बताया कि उनके वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र के नवीनीकरण व ऑनलाइन करने से संबंधित शिकायत का विभाग द्वारा समाधान कर दिया गया है। कृषि विभाग से संबंधित सब्सिडी के प्रकरण पर उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना से जुड़े परिवादों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कर किसानों एवं दुग्ध उत्पादकों को समय पर राहत पहुंचाएं।

'इण्डियाज इन्टरनेशनल मूवमेंट टू यूनाईट नेशन' में राज्यपाल ने सम्बोधित किया

बौद्धिक क्षमताओं के विकास से युवा समृद्ध,संपन्न होंगेःराज्यपाल

पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं

जयपुर (नि.सं.)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि शिक्षा को विवेक, समझदारी और ज्ञान से जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने का अर्थ जीवन में सफल होना नहीं है। जीवन की सफलता बौद्धिक क्षमताओं के विकास से होती है। उन्होंने कहा कि कर्तव्य की भावना का विकास हर व्यक्ति में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस भावना से ही जवाबदेही बढ़ेगी। राज्यपाल बागडे एक निजी विश्वविद्यालय में 'इण्डियाज इन्टरनेशनल मूवमेंट टू यूनाईट नेशन' के अंतर्गत ज़ेन जेड और ज़ेन अल्फा द्वारा शिक्षा और समाधान विषयक संवाद में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण पाया है। इसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों को प्रतिभाशाली बनाना है तो सामान्य ज्ञान से विद्यार्थी जुड़े। इसी से बच्चे बौद्धिक रूप में विकसित हो सकेंगे। राज्यपाल ने कहा कि युवा उच्च शिक्षा के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने आपको तैयार करें। उन्होंने कहा कि महिला पुरुष में अब भेद नहीं रह गया है। महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। उन्होंने कहा कि आज लड़कियां लड़कों से शिक्षा में अधिक अच्छा प्रदर्शन कर रहीं है। उन्होंने कमला भागवत सोहनी का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें मुंबई विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। अपने प्रयासों से वह पहली भारतीय महिला हुई जिसने भारत में सबसे पहले पीएचडी की। उन्होंने





खाद्य पदार्थों में मौजूद प्रोटीनों पर काम किया, और अनुसंधान में सेल्यूलर एंजाइम साइटोक्रोम सी की खोज की। उन्होंने कहा कि महिलाएं आत्मबल मजबूत रखे। इसी से वे जीवन में निरंतर आगे बढ़ सकेंगी। बागडे ने कहा कि पेपर लीक की स्थितियां नहीं हो, इसके लिए कानूनी कार्यवाही ही पर्याप्त नहीं है। जीवन में नैतिकता, ईमानदारी, प्रामाणिकता होगी तो पेपर लीक नहीं होंगे। यह सब जीवनगत संस्कार है। इनसे जुड़ी शिक्षा से युवाओं को जुड़ना चाहिए। युवा पाठ्य पुस्तकें ही नहीं पढ़े बल्कि सामाजिक सरकारों से जुड़े ज्ञान के लिए भी प्रयासरत रहें। उन्होंने कहा कि ईमानदारी, नैतिकता हर व्यक्ति के मन में होना जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि भारत के लोगों के पास नैतिकता आरम्भ से रही है। परन्तु अंग्रेजों के आने के बाद जो शिक्षा पद्धति लॉर्ड मैकाले ने प्रारम्भ की उससे जीवन में मूल्य गौण होते चले गये।

बागडे ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ही नहीं उनका संरक्षण भी करें। अधिक गर्मी से बचाव का एक मात्र उपाय पेड़ ही हैं। उन्होंने कहा कि भले ही सौ एकड़ की जगह दस एकड़ में ही पेड़ लगाएं पर जो पेड़ लगाएं वह बचे रहे, इसका प्रयास जरूर करें। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए सभी बच्चों को आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने भावी पीढ़ियों के लिए हर बच्चे को पेड़ लगाने और उनकी सार संभाल करने की आवश्यकता जताई।

गहलोत बोले- पुलिस अफसर कह रहे निकाय-चुनाव में दबाव था

सीएमओ से हो रही थी रोज मॉनिटरिंग; कहा- कई जिलों में अकाल की स्थिति



जयपुर। जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा- चुनाव हारना-जीतना चलता रहता है, उसकी हमें चिंता नहीं है। परिसीमन में जो बेईमानी हुई और उसके ऊपर पुलिस की जो गुंडागर्दी रही, वह चिंताजनक है। गहलोत ने कहा- पुलिस अधिकारी अब खुद कह रहे हैं कि हम पर भारी दबाव था। सीएमओ से रोज मॉनिटरिंग हो रही थी और मुख्यमंत्री ने खुद एसपी-कलेक्टर को बुला-बुलाकर निर्देश दिए थे। गहलोत ने जयपुर में अपने सरकारी आवास पर मीडिया से रविवार को बात करते हुए यह सब कहा। गहलोत ने एक बार फिर निकाय चुनाव में पुलिस प्रशासन के दुरुपयोग और गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए यह कहा। गहलोत ने कहा- अब पंचायत चुनाव आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संभाग, जिला और विधानसभा स्तर पर कमेटियां बना दी हैं, पर्यवेक्षक लगा दिए हैं। हम पूरी मजबूती से ये चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पंचायत में भी परिसीमन बेईमानी से किया गया है और बाड़ेबंदी की छूट दे दी गई है। ये लोग बाड़ेबंदी में उस्ताद हैं और कैश बांटने के लिए इनके पास बहुत पैसा है, लेकिन जनता इन्हें जरूर जवाब देगी। लोग सब देख और समझ रहे हैं। वहीं गहलोत ने कहा- मैं हाल ही बीकानेर गया था, वहां अकाल की स्थिति बहुत गंभीर है। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जैसे क्षेत्रों में भी अकाल के हालात बेहद चिंताजनक बन चुके हैं। यदि मुख्यमंत्री स्तर पर मॉनिटरिंग कर समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो पूरे प्रदेशवासियों को भारी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा।

गलत बयानी कर रहे मुख्यमंत्री

अशोक गहलोत ने कहा- यह अपनी गुंडागर्दी को कितना ही छिपाने की कोशिश करें, उसका खंडन करें। वास्तव में इससे राजस्थान की बहुत बदनामी हुई है। मीडिया में इस पर डिस्कशन हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गलत बयानी कर रहे हैं।

गहलोत ने कहा- परिसीमन में इन्होंने पूरे राजस्थान में बेईमानी की है। मैंने सुना है कि घनश्याम तिवाड़ी, राजेंद्र राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी ने छह महीने तक ओटीएस में बैठकर यही काम किया और पूरा बर्बाद कर दिया। वार्डों की संख्या का मजाक बना दिया। कोई वार्ड 85 वोटर्स का है, कोई 250 का, तो कोई 5 हजार, 10 हजार और 20 हजार तक का है। आप इस तरह लोकतंत्र की हत्या क्यों कर रहे हैं?

वन-वे के विरोध में 4 बाजार बंद, व्यापारियों का मार्च

हवामहल, चांदी की टकसाल, सुभाष चौक और पुराने आमेर रोड के व्यापारी उतरे सड़क पर



जयपुर। परकोटे में हवामहल के सामने शुरू की गई वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था का विरोध शनिवार को चार बाजारों तक फैल गया। व्यवस्था लागू होते ही व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दीं और सड़क पर उतरकर अधिकारियों व सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने पैदल मार्च निकालकर वन-वे व्यवस्था का विरोध किया। इसमें हवामहल, चांदी की टकसाल, सुभाष चौक और पुराने आमेर रोड के व्यापारी शामिल हुए। व्यापारियों का कहना था कि सुभाष चौक से हवा महल की ओर जाने वाले रूट को डायवर्ट करने से बाजार में ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है। इससे कारोबार प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों ने कहा कि पर्यटक सीजन में जब बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़नी चाहिए, तब वन-वे व्यवस्था के कारण व्यापार पर संकट खड़ा हो गया है।

व्यापारियों के विरोध की सूचना मिलने पर जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल और महामंत्री सुरेश सैनी मौके पर पहुंचे। उन्होंने सिरढ़ोडी व्यापार मंडल के अध्यक्ष विनय प्रकाश से बातचीत की। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों से भी बात की गई। सुभाष चौक व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल और महामंत्री महावीर शर्मा के नेतृत्व में व्यापारियों ने विरोध जारी रखा। मौके पर पहुंचे ट्रैफिक पुलिस डीसीपी हरी प्रसाद सोमानी ने व्यापारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन व्यापारी वन-वे व्यवस्था में बदलाव की मांग पर अड़े रहे। आखिरकार व्यापारियों के विरोध के बाद शाम 4 बजे ट्रैफिक पुलिस को व्यवस्था बदलनी पड़ी। वन-वे व्यवस्था खत्म कर रूट पर टू-वे ट्रैफिक शुरू किया गया।

विधानसभा अध्यक्ष ने उदयपुर स्थित नौ देवी मंदिरों में किये दर्शन

जयपुर(नि.सं.)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी उदयपुर के एक दिवसीय दौरे पर रहे। देवनानी ने शहर के नौ देवी मंदिरों में नव माता दर्शन कर प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि देवी के आशीर्वाद से देश के युवाओं की सर्जन शक्ति में बढ़ोतरी हो और उन्हें अराजकता से दूर रहते हुए देश की समृद्धि में अपना योगदान देनें की प्रेरणा मिले। साथ ही, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान की भावना उत्तरोत्तर बढ़ती रहे।



शिशु संजीवनी का किया शुभारंभ

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विद्याधर नगर आंगनवाड़ी में किया कन्या पूजन





जयपुर(नि.सं.)। उप मुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने विद्याधर नगर की आंगनबाड़ी में कन्या पूजन कर कन्याओं को हलवा खिलाया और उन्हें उपहार भेंट किये। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आंगनबाड़ी केंद्र का अवलोकन भी किया तथा शिशु संजीवनी पोषण आहार का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि विटामिन एवं खनिजों से समृद्ध पोषण से भरपूर यह पूरक आहार शिशु संजीवनी 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में दो बार दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस अवसर पर कहा कि नंद घर वेदांता के सहयोग से बच्चों को यह पूरक आहार उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक सशक्त राजस्थान की नींव स्वस्थ बच्चों और सशक्त बेटियों से ही रखी जा सकती है। राज्य सरकार चाहती है कि छोटे बच्चों की सामयिक वृद्धि, समुचित विकास और उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित किया जाए। बाल पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल को बेहतर बनाने के लिए नंद घर की ओर से भी प्रयास किये जा रहे हैं।

'आश्रम 4' की शूटिंग पूरी कर लौटे अभिनेता जहांगीर खान

जयपुर एयरपोर्ट पर कई सेलेब्रिटीज दिखे; सिंगर सुरेश वाडकर और अफसाना खान आज देंगे लाइव परफॉर्मेंस



जयपुर। जयपुर एयरपोर्ट पर रविवार को सेलेब्रिटीज की आवाजाही देखने को मिली। लीजेंड्री सिंगर सुरेश वाडकर अपनी पत्नी के साथ जयपुर पहुंचे, वहीं पंजाबी गायिका अफसाना खान भी शहर में लाइव परफॉर्मेंस देने के लिए आईं। दूसरी ओर अभिनेता जहांगीर खान पिछले करीब एक महीने से जयपुर और आसपास की अलग-अलग लोकेशन पर वेब सीरीज 'आश्रम 4' की शूटिंग करने के बाद लौटे। तीनों कलाकारों की मौजूदगी से शहर में मनोरंजन जगत से जुड़ी गतिविधियां चर्चा में रहीं।

सुरेश वाडकर अपनी सुरीली आवाज और शास्त्रीय संगीत की मजबूत पकड़ के लिए पहचाने जाते हैं। जयपुर में होने वाले कार्यक्रम में वे गजल, शास्त्रीय संगीत, बॉलीवुड के लोकप्रिय गीतों और भजनों की प्रस्तुति देंगे। वहीं अफसाना खान पंजाबी संगीत की अपनी खास आवाज और ऊर्जावान मंचीय प्रस्तुतियों के लिए जानी जाती हैं।

सुरेश वाडकर की आवाज में गूंजेंगे बॉलीवुड गीत और भजन

भारतीय संगीत जगत में अपनी अलग पहचान रखने वाले सुरेश वाडकर का गायन शास्त्रीय संगीत की बारीकियों और भावपूर्ण अंदाज के लिए जाना जाता है। उन्होंने हिंदी और मराठी फिल्मों के साथ-साथ भक्ति संगीत के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। जयपुर में होने वाली उनकी प्रस्तुति में संगीत की अलग-अलग विधाओं का संगम देखने को मिलेगा।

सुरेश वाडकर के फिल्मी गीतों की बात करें तो 'प्रेम रोग' का 'मेरी किस्मत में तू नहीं शायद', 'चांदनी' का 'लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है', 'राम तेरी गंगा मैली' का 'हुस्न पहाड़ों का' और 'परिंदा' का 'तुमसे मिलके ऐसा लगा' जैसे गीत आज भी श्रोताओं के बीच लोकप्रिय हैं। इन गीतों में उनकी आवाज का भावपूर्ण अंदाज सुनने को मिलता है। इसके अलावा 'उत्सव' का 'सांझ ढले गगन तले' और 'दिल' का 'ओ प्रिया प्रिया' भी उनके चर्चित गीतों में शामिल हैं।

संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए सुरेश वाडकर को पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जैसे सम्मान मिल चुके हैं।

'तितलियां' से देशभर में पहचान बनाने वाली अफसाना खान

पंजाबी गायिका अफसाना खान भी जयपुर में लाइव परफॉर्मेंस देने पहुंची हैं। अपनी दमदार आवाज के लिए पहचानी जाने वाली अफसाना ने पंजाबी संगीत जगत में अपनी अलग जगह बनाई है। अफसाना खान ने वर्ष 2012 में गायन रियलिटी शो 'वॉइस ऑफ पंजाब' के तीसरे सीजन में हिस्सा लेकर अपने करियर की शुरुआत की थी।

इस शो में वह शीर्ष पांच प्रतिभागियों में शामिल हुईं। इसके बाद वर्ष 2017 में वह 'राइजिंग स्टार' के पहले सीजन में नजर आई और शीर्ष सात प्रतिभागियों तक पहुंचीं। अफसाना को देशभर में बड़ी पहचान गीत 'तितलियां' से मिली। सिद्धू मूसेवाला के साथ उनके गाने 'धक्का' ने भी खूब चर्चा बटोरी। इसके अलावा 'जानी वे जानी', 'बाजार' और 'धोखेबाज' जैसे गानों के जरिए उन्होंने अपनी गायकी का दायरा बढ़ाया।

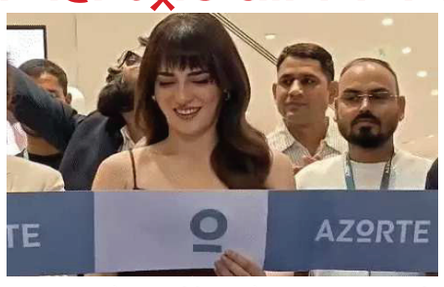
'आश्रम 4' की शूटिंग के लिए एक महीने जयपुर में रहे जहांगीर खान

अभिनेता जहांगीर खान भी जयपुर एयरपोर्ट पर नजर आए। वह पिछले करीब एक महीने से जयपुर और आसपास की विभिन्न लोकेशन पर वेब सीरीज 'आश्रम 4' की शूटिंग में व्यस्त थे। शूटिंग पूरी होने के बाद अब वह शहर से लौटे हैं। सीरीज में वह अहम किरदार निभा रहे हैं। प्रकाश झा के निर्देशन में बनी 'आश्रम' सीरीज में बॉबी देओल बाबा निराला के किरदार में नजर आते हैं। कहानी और इसके किरदारों ने सीरीज को दर्शकों के बीच खास पहचान दिलाई है।

जहांगीर खान इससे पहले 'पान सिंह तोमर', 'दिलवाले' और 'गंगूबाई काठियावाड़ी' जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। वह फिल्मों और वेब सीरीज में अलग-अलग भूमिकाओं के जरिए अभिनय करते रहे हैं। 'आश्रम' से उनका जुड़ाव भी उनके करियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

राधिका मदान बोलीं-जयपुर मेरे लिए हमेशा लकी रहाःयहां स्ट्रीट शॉपिंग करना पसंद

आम दिनों में जींस और हुडी पहनना पसंद



जयपुर(नि.सं.)। एक्ट्रेस राधिका मदान ने मानसरोवर स्थित पैसिफिक मॉल में प्रीमियम फैशन एवं लाइफस्टाइल ब्रांड अझॉर्ट के 47वें स्टोर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने फैशन को लेकर अपनी पसंद, जयपुर से अपने जुड़ाव और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बातचीत की। राधिका ने कहा कि जयपुर में उन्हें हमेशा प्यार और अपनापन मिला है। यह शहर उनके लिए हमेशा लकी रहा है। यहां आकर उन्हें एक खास तरह का जुड़ाव महसूस होता है। इस मौके पर राधिका ने ब्रांड के कलेक्शन को भी देखा और अपनी पसंद के कपड़ों की खरीदारी की। उन्होंने बताया कि उन्हें इंडियन और वेस्टर्न, दोनों तरह के कपड़े पहनना पसंद है। एक अभिनेत्री होने के नाते अलग-अलग तरह के लुक्स और आउटफिट्स पहनने का मौका मिलता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी पसंद काफी सहज रहती है। आम दिनों में वह जींस और हुडी पहनना पसंद करती हैं। स्टोर लॉन्च के दौरान ब्रांड की हियर फॉर द लुक्स सोच को भी सामने रखा गया। इसी थीम पर आयोजित फैशन शो में अझॉर्ट के नए कलेक्शन को रैंप पर पेश किया गया।

औचक निरीक्षण **जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया निरीक्षण**

चिह्नित मतदाता सूचियों की कार्यकारी प्रतियों के जांच कार्य का किया जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया निरीक्षण

794 मतदान केंद्रों के लिए होगी 7094 मतदाता सूचियां तैयार

जयपुर(नि.सं.)। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने प्रथम चरण के लिए जिला सांख्यिकी कार्यालय में चल रही मतदाता सूचियों के जांच कार्य का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रथम चरण में झोटवाड़ा, किशनगढ़-रेनवाल, जोबनेर, चौमूं, दूदू, मौजमाबाद, सांभर व गोविन्दगढ़ पंचायत समितियों के कुल 794 मतदान केंद्रों हेतु कुल 7940 मतदाता सूचियों की जांच चिह्नित मतदाता प्रकोष्ठ में चल रहे कार्य



का बारीकी से निरीक्षण किया एवं कार्मिकों को मतदाता सूचियों में विलोपित सूची को लाल स्याही से क्रॉस करने के निर्देश दिए।

उन्होंने मतदाता सूचियों की गहनता से जांच करने के निर्देश भी प्रदान किए। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर चतुर्थ आशीष कुमार, उप जिला अधिकारी मेघराज सिंह मीणा, सांख्यिकी विभाग के संयुक्त निदेशक एवं प्रभारी अधिकारी सांख्यिकी प्रकोष्ठ बाबूलाल मीणा सहित चुनाव कार्य में लगे हुए अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे।

جنتر منتر متاثرین کی آواز سننے کیلئے سپریم کورٹ کی کمیٹی متحرک

● شکایات وشواہد حاصل کرنے کے لیے پورٹل کا آغاز
● پیلیٹ گن کے استعمال، خاتون مظاہرین کو ہراساں کرنے اور پولیس زیادتیوں کی تحقیقات

آوازِ تسنیم: جنتر منتر پر طلبہ کے احتجاج کے دوران تشدد اور پولیس کی مبینہ زیادتیوں کے الزامات کی جانچ اب ایک اہم مرحلے میں داخل ہوگئی ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے تشکیل کردہ اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی نے متاثرین اور عینی شاہدین کی شکایات، بیانات اور شواہد حاصل کرنے کے لیے آن لائن پورٹل شروع کر دیا ہے۔ اس اقدام کے تحت پولیس اور دیگر سکیورٹی اہلکاروں سمیت تمام متاثرہ افراد اپنے ساتھ پیش آئے واقعات کی تفصیلات کمیٹی تک پہنچا سکتے ہیں۔ مرکزی وزارت داخلہ کے مطابق، تحقیقات میں پیلیٹ گن کے استعمال، خواتین مظاہرین کو نشانہ بنانے اور ہراساں کرنے، نیز دونوں جانب سے ضرورت سے زیادہ تشدد اور املاک کو نقصان پہنچانے کے معاملات کو ترجیح دی جائے گی۔ کمیٹی سپریم کورٹ کے 18 اگست اور 10 ستمبر 2026 کے احکامات میں درج امور کا جائزہ لے گی۔ ان میں پیلیٹ گن اور برقی لاٹھیوں کا استعمال، مظاہرین اور پولیس اہلکاروں کے خلاف تشدد، متاثرین کو معاوضے کی ادائیگی اور مخصوص افراد کو نشانہ بنانے کے الزامات شامل ہیں۔ شکایات درج کرانے کے لیے پورٹل http://hpec.nic.in شروع کیا گیا ہے۔ آن لائن پورٹل پر شکایات درج کرانے کے لیے مختلف زمرے بنائے گئے ہیں۔ متاثرین، بشمول پولیس اہلکار، اپنے ساتھ پیش آئے واقعات کی تفصیلات پیش کرسکتے ہیں؛ عینی شاہدین اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر معلومات فراہم کرسکتے ہیں؛ دیگر افراد خفیہ طور پر شواہد پیش کرسکتے ہیں اور کمیٹی کو تجاویز بھی دے سکتے ہیں۔ شکایت کے ساتھ دستاویزات، تصاویر، ویڈیوز، زخموں کی تصاویر اور طبی رپورٹیں بھی منسلک کی جاسکتی ہیں۔ شکایت کنندگان سے یہ بھی دریافت کیا جاتا ہے کہ آیا متاثرہ شخص کو جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وزارت داخلہ کے مطابق، پورٹل کو اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ حساس نوعیت کے معاملات میں گواہوں کو تحفظ فراہم کیا جاسکے اور متاثرین کی خواہش پر ان کی شناخت خفیہ رکھی جائے۔ آن لائن سہولت کے علاوہ شکایات کمیٹی کے دفتر، شکشا سدن، 17 راؤز ایونیو انسٹی ٹیوشنل ایریا، نئی دہلی میں کام کے دنوں میں دوپہر 2 بجے سے شام 4 بجے تک پیش کی جاسکتی ہیں۔ شکایات ڈاک کے ذریعے یا hpec2026.enquiry@nic.in پر ای میل کرکے بھی بھیجی جاسکتی ہیں۔ جولائی کے احتجاج کے دوران پیلیٹ گن کے مبینہ استعمال نے کئی سنگین سوالات کھڑے کردیے تھے۔ الزام ہے کہ دہلی پولیس کی کمان میں کام کرنے والی سی آر پی ایف کی ریپڈ ایکشن فورس نے مظاہرین پر پیلیٹ فائر کیے۔ اگرچہ پیلیٹ گن کو ہجوم پر قابو پانے کے لیے استعمال ہونے والے آلات میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن طلبہ مظاہرین کے خلاف اس کے استعمال پر اپوزیشن جماعتوں، طلبہ اور ماہرین نے سخت اعتراضات اٹھائے تھے۔ دہلی میں اس نوعیت کے استعمال کا یہ پہلا واقعہ بتایا گیا، جب کہ جموں وکشمیر میں پیلیٹ گن کے استعمال کے نتیجے میں متعدد افراد کی بینائی متاثر ہونے کے واقعات پہلے ہی شدید تنازع کا سبب بن چکے ہیں۔ دستیاب اطلاعات کے مطابق، کم ازکم چار افراد، شیخ ارشاد منصوری (25)، نوٹن ٹوپو (32)، ایک 28 سالہ صحافی اور ساحل لو چاب (19)، کو پیلیٹ سے زخم آئے تھے۔ پولیس اور سی آر پی ایف نے اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، تاہم طبی وقانونی رپورٹوں میں پیلیٹ کے زخموں کی تصدیق کی گئی ہے۔ ساحل لو چاب کے معاملے میں 21 اگست کو دہلی پولیس نے ایف آئی آر درج کی۔ اس سے قبل کانگریس رہنما راہل گاندھی نے پولیس اسٹیشن میں دھرنا دیا تھا اور الزام لگایا تھا کہ دو شکایات موصول ہونے کے باوجود ابتدائی طور پر مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے 18 اگست کو سابق جج آر سبھاش ریڈی کی سربراہی میں پانچ رکنی اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی تھی۔ عدالت نے 20 جولائی کے طلبہ احتجاج کے دوران پولیس اور سکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے طاقت کے مبینہ حد سے زیادہ اور غیر متناسب استعمال کے الزامات کو آزادانہ اور غیر جانب دارانہ تحقیقات کے لیے کافی اہم قرار دیا تھا۔ ساتھ ہی پولیس اہلکاروں کے خلاف تشدد اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے الزامات کی جانچ کی ذمہ داری بھی کمیٹی کو سونپی گئی۔ تحقیقات کا دائرہ محض احتجاج کے دوران پیش آئے واقعات تک محدود نہیں ہے۔ کمیٹی کو ہجوم پر قابو پانے کی کارروائیوں کے دوران سکیورٹی اہلکاروں کے لیے یونیفارم کی پابندی، عمومی امتناعی احکامات کے نفاذ، پولیس کی نگرانی کے قانونی جواز اور بھارتیہ نیائے سنہتا کی ایک دفعہ کے ذریعے اختلافِ رائے کو دبانے کے الزامات کا بھی جائزہ لینا ہے۔



نئی دہلی میں احتجاج کے دوران پولیس تشدد کا نشانہ بننے والے طلباء اور خواتین سے کانگریس قائد راہول گاندھی کی ملاقات کا منظر

حکومت بدلنے کا وقت آ گیا ہے: کپل سبل

راج ناتھ سنگھ کے الزام پر ممتاز وکیل کا جوابی وار



آوازِ تسنیم: راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ کپل سبل نے کانگریس پر حکومت کی تبدیلی سے متعلق الزامات عائد کرنے پر مرکزی وزیر راج ناتھ سنگھ پر جوابی حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دراصل ملک کے عوام حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں اور اب اس حکومت کے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ کپل سبل کا یہ بیان راج ناتھ سنگھ کے اس بیان کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں کے خلاف قومی دارالحکومت میں ہونے والے مظاہروں پر کانگریس اور اس کے اتحادیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ راج ناتھ سنگھ نے اپوزیشن پر بنگلہ دیش کی طرز پر حکومت تبدیل کرنے اور نوجوانوں کی توانائی کو انتشار پھیلانے کے لیے استعمال کرنے کا الزام لگایا تھا۔ لکھنؤ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے راج ناتھ سنگھ نے کہا تھا کہ جمہوریت کسی کو بھی انتشار پھیلانے یا دستوری اداروں کے وقار کو مجروح کرنے کا پروانہ نہیں دیتی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کپل سبل نے کہا کہ راج ناتھ سنگھ کا یہ الزام غلط ہے کہ کانگریس بنگلہ دیش کے راستے حکومت کی تبدیلی چاہتی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خود عوام حکومت کی تبدیلی کے خواہاں ہیں۔ آزاد رکن پارلیمنٹ نے مزید کہا کہ انڈیا اگینسٹ کرپشن کے نعرے تلے ہونے والے مظاہروں نے آپ (بی جے پی/این ڈی اے) کو اقتدار دلایا تھا لیکن اقتدار میں آنے کے بعد آپ نے بدعنوانی کو گلے لگالیا، اداروں پر قبضہ کرلیا اور ووٹر لسٹ میں ہیرا پھیری کی، اب آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس سے قبل جمعہ کے روز راج ناتھ سنگھ نے الزام لگایا تھا کہ کانگریس اور اس کے سیاسی اتحادی براہ راست اور اپنی حمایتی تنظیموں کے ذریعے نوجوانوں کی طاقت کو تعمیری کاموں اور قوم کی تعمیر میں لگانے کے بجائے سیاسی تصادم اور انارکی پھیلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ملک کے نوجوانوں کو انتشار کی سیاست میں مہرہ بنایا جا رہا ہے، اور الزام لگایا کہ کانگریس اور اس کے حلیف بنگلہ دیش کی طرز پر اقتدار کی تبدیلی چاہتے ہیں۔

منی بس گہری کھائی میں گر گئی
8 افراد ہلاک، 15 زخمی

آوازِ تسنیم: مسافرین کو لے جانے والی ایک بس حادثہ کا شکار ہوگئی، جس کی وجہ سے 8 افراد ہلاک اور 15 دوسرے زخمی ہوگئے، جن میں 8 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ یہ واقعہ دہلی۔ممبئی ایکسپریس وے راجستھان کے ضلع کوٹہ کے قریب آج صبح 6 بجے پیش آیا۔ ذرائع نے بتایا کہ منی بس جس میں تقریباً 23 مسافرین سوار تھے، سڑک سے پھسل گئی اور 15 فٹ گہری کھائی میں گرگئی۔ یہ حادثہ پول نمبر 384 کے قریب ایکسپریس وے پر پیش آیا۔ حکام نے شبہ کیا ہے کہ ڈرائیور کے حالتِ نیند میں ہونے کی وجہ سے بس قابو سے باہر ہوگئی۔

عمران خان کا 'ہندوستان چھوڑ' نوٹس کو چالنج

وجوہات بتائی گئیں نہ جواب کا موقع دیا گیا۔ معروف اداکار کا ادعا



آوازِ تسنیم: معروف اداکار عمران خان نے 28 اکتوبر سے قبل ہندوستان چھوڑنے کے نوٹس کو بمبئی ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ ان کی عرضی میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ انہیں جاری کیے گئے نوٹس میں نہ تو کسی قسم کی وجوہات واضح کی گئی ہیں اور نہ ہی مبینہ خلاف ورزیوں کے حوالے سے جواب دینے کا کوئی موقع دیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کا مطالبہ کرنے والے ممبئی احتجاج میں شرکت کے چند روز بعد اداکار عمران خان کو جمعرات کے روز فارینرز ریجنل رجسٹریشن آفس (ایف آر آر او) کے ممبئی دفتر کی جانب سے ہندوستان چھوڑنے کا نوٹس موصول ہوا تھا۔ اس نوٹس میں 43 سالہ اداکار کو امریکی شہری قرار دیا گیا ہے اور انتباہ دیا گیا ہے کہ اگر وہ مقررہ تاریخ سے قبل ہندوستان چھوڑنے میں ناکام رہے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پی ٹی آئی کے مطابق بمبئی ہائی کورٹ میں دائر کردہ اپنی درخواست میں عمران خان نے اس نوٹس کو غیر قانونی، غیر معقول اور قانون کے منافی قرار دیا ہے۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ یہ نوٹس بغیر کوئی وجہ بتائے، بغیر ثبوتی مواد پیش کیے اور بغیر کسی مخصوص قانونی خلاف ورزی کی نشاندہی کے جاری کیا گیا ہے۔ نوٹس کسی باضابطہ تحقیقات، وجہ بتاؤ نوٹس یا درخواست گزار کو مبینہ الزامات پر صفائی کا موقع فراہم کیے بغیر جاری کیا گیا۔ عمران خان کو جاری کیے گئے نوٹس میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے امیگریشن اینڈ فارینرز ایکٹ 2025 کے ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے۔ تاہم عمران خان کی درخواست کے مطابق موجودہ قانون یا قواعد کے تحت ایسی کوئی دفعہ موجود نہیں ہے جو اوورسیز سٹیزن آف انڈیا (او سی آئی) کارڈ ہولڈر کو کسی پرامن احتجاج میں حصہ لینے سے روکتی ہو۔ واضح رہے کہ عمران خان نے 10 اکتوبر کو ممبئی کے اگست کرانتی میدان میں چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفیٰ کے لیے ہونے والے ایک احتجاج میں شرکت کی تھی۔ اس مظاہرے کے دوران انہیں کچھ دیر کے لیے حراست میں بھی لیا گیا تھا اور اس کے چند روز بعد ایف آر آر او کا یہ نوٹس جاری کر دیا گیا۔ شہریت ایکٹ 1955 کے تحت اوورسیز سٹیزن آف انڈیا (او سی آئی) کارڈ رکھنے والوں کے لیے مخصوص قواعد مقرر ہیں۔ عمران خان کے پاس یہی کارڈ موجود ہے جو کہ ہندوستانی نژاد غیر ملکی شہریوں اور ہندوستانی شہریوں کے غیر ملکی شریک حیات کو جاری کیا جاتا ہے۔ بیورو آف امیگریشن نے وضاحت کی ہے کہ او سی آئی کارڈ ہولڈرز ہندوستان کے شہری نہیں ہیں، نہ وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں اور نہ ہی دستوری عہدوں پر فائز ہو سکتے ہیں۔ بیورو نے ایک تفصیلی بیان میں او سی آئی کارڈ ہولڈرز کے حقوق اور پابندیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہندوستان میں ووٹ دینے کے حقدار نہیں ہیں، وہ اسمبلی، قانون ساز کونسل یا پارلیمنٹ کے رکن نہیں بن سکتے اور نہ ہی صدر جمہوریہ، نائب صدر، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج جیسے دستوری عہدوں پر فائز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مرکزی یا ریاستی امور سے متعلق سرکاری ملازمتوں اور خدمات پر تقرری کے اہل نہیں ہیں اور انہیں ہندوستان میں زرعی زمین، فارم ہاؤس یا باغات کی جائیدادیں خریدنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اداکار کی درخواست پر چیف جسٹس مہیش چندر ترپاٹھی اور جسٹس ادویت سیٹھنا پر مشتمل ڈویژن بنچ کے روبرو فوری سماعت کے لیے ذکر کیے جانے کا امکان ہے۔

پریا گولڈ بسکٹ میں مویشیوں کے چارے کی بھوسی کا استعمال

فوڈ ریگولیٹر کی قانونی کارروائی۔ ڈوڈلا سمیت دیگر 2 کمپنیاں بھی زد میں



آوازِ تسنیم: فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز اتھارٹی آف انڈیا نے پریا گولڈ بسکٹ کی تیاری میں مویشیوں کے چارے والی بھوسی کے استعمال اور دیگر سنگین خلاف ورزیوں پر سوریا فوڈ اینڈ ایگرو کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ قواعد وضوابط کی سنگین خلاف ورزیوں پر ڈوڈلا ڈیری اور یو ای آئی آر آرگینک فوڈز کے خلاف بھی مقدمہ چلانے کے قانونی اقدامات کا آغاز کیا گیا ہے۔ پریا گولڈ بسکٹ فروخت کرنے والی کمپنی سوریا فوڈ اینڈ ایگرو کے خلاف یہ کارروائی بسکٹ کی تیاری میں مویشیوں کے چارے والی بھوسی کے استعمال پر کی گئی ہے۔ دوسری جانب ڈوڈلا ڈیری کے فل کریم دودھ کا نمونہ غیر معیاری پایا گیا جبکہ یو ای آئی آر آرگینک فوڈز کی جانب سے فروخت کی جانے والی زرد کشمش میں کیڑے مار ادویات کے باقیات پائے گئے۔ ہفتہ کے روز سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں فوڈ سیفٹی ریگولیٹر نے مطلع کیا کہ اس نے غذائی تحفظ کی سنگین خلاف ورزیوں پر ان تینوں کمپنیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی شروع کر دی ہے۔ سوریا فوڈ اینڈ ایگرو کے معاملے میں ریگولیٹر نے پایا کہ کمپنی پریا گولڈ بسکٹ کی تیاری میں مویشیوں کی بھوسی کا استعمال کر رہی تھی۔ ایک صارف کی شکایت پر ادارے نے کمپنی کے مینوفیکچرنگ یونٹ کا معائنہ کیا جہاں غذائی تحفظ اور صفائی ستھرائی کی سنگین خامیاں سامنے آئیں۔ ریگولیٹر نے بتایا کہ معائنے کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ پریا گولڈ بسکٹ کی تیاری میں فائبر کے حصول کے لیے خام مال کے طور پر ایسی بھوسی استعمال کی جا رہی تھی جو دراصل مویشیوں کے چارے کے لیے مخصوص ہے اور انسانی استعمال کے لیے قطعاً موزوں نہیں ہے۔

شیر خوار بچوں کی غذا میں مصنوعی شکر کی شمولیت پر پابندی کی تجویز

آوازِ تسنیم: فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز اتھارٹی آف انڈیا نے چھ ماہ تک کی عمر کے شیر خوار بچوں کے لیے تیار کی جانے والی غذائی اشیاء میں فرکٹوز اور سوکروز (شکر) کی شمولیت پر پابندی عائد کرنے کی تجویز پیش کی ہے، جس کا اعلان ہفتہ کے روز ایک سرکاری بیان میں کیا گیا۔ وزارت صحت اور خاندانی بہبود کے بیان کے مطابق اس اقدام کا مقصد نوزائیدہ بچوں کے لیے غذائی تحفظات کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اس پیشرفت کو شیئر کرتے ہوئے ادارے نے لکھا کہ اس کا مقصد شیر خوار بچوں کے غذائی معیارات کو بہتر بنانا ہے تاکہ چھ ماہ تک کے بچوں کے کھانے پینے کی اشیاء میں سوکروز اور فرکٹوز کے اضافے پر روک لگائی جا سکے۔ مجوزہ ترمیمی مسودے کا بنیادی مقصد زندگی کے ابتدائی ایام میں بچوں کو اضافی شکر کے اثرات سے محفوظ رکھنا ہے۔ فوڈ ریگولیٹر نے فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز (فوڈز فار انفینٹ نیوٹریشن) ریگولیشنز 2020 میں ترمیمی مسودہ شائع کیا ہے جس میں چھ ماہ تک کی عمر کے بچوں کی مصنوعات میں شکر اور فرکٹوز ملانے پر ممانعت کی تجویز دی گئی ہے۔ یہ نوٹیفکیشن عوامی مشاورت کے لیے جاری کیا گیا ہے اور متعلقہ فریقین اور اسٹیک ہولڈرز 60 دن کے اندر اپنے اعتراضات اور تجاویز پیش کر سکتے ہیں۔ وزارت کے بیان کے مطابق فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز (فوڈز فار انفینٹ نیوٹریشن) ترمیمی ضوابط 2026 کا مقصد موجودہ ریگولیٹری ڈھانچے کو مضبوط بنانا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ بچوں کی غذائی مصنوعات ان کی عمر کے تقاضوں کے عین مطابق تیار کی جا رہی ہیں۔

بعض قائدین 'وکست بھارت' کے مخالف: یوگی

چیف منسٹر اترپردیش یوگی آدتیہ ناتھ نے آج یہاں کہا کہ حکومت ''وکست بھارت'' نظریہ کو روبہ عمل لانے کی ممکنہ کوشش کر رہی ہے۔ اس سلسلہ میں بعض افراد رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ''وکست بھارت'' نظریہ کے مخالف ہیں۔ ڈاکٹر رام منوہر لوہیا نیشنل لا یونیورسٹی لکھنؤ کے پانچویں جلسۂ تقسیم اسناد کو مخاطب کرتے ہوئے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ ہندوستان کی ترقی کے لیے وکست بھارت نظریہ پر عمل آوری کی جارہی ہے لیکن بعض طاقتیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ ہندوستان کے کئی کروڑ شہریوں کی صورتِ حال کو بہتر بنانے کے لیے حکومت ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ حکومت کی کوششوں اور اقدامات میں اشتراک وتعاون کرنا چاہیے، لیکن اس کی مخالفت کی جارہی ہے، جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بعض طاقتیں حکومت کے ترقیاتی اقدامات میں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہیں۔ بعض افراد کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ وکست بھاریت کے مخالف اور ضی ہیں۔ آدتیہ ناتھ نے ایمر جنسی کے نفاذ پر کانگریس حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ 1975 میں ہندوستان میں ایمرجنسی نافذ کی گئی، جس کے دوران استبدادی اقدامات کیے گئے تھے۔

بھڑوچ گجرات کی کیمیکل فیکٹری میں دھماکہ، 5 ہلاک

گجرات کے ضلع بھڑوچ میں ایک کیمیکل فیکٹری دھماکہ میں پانچ ورکر ہلاک اور دیگر 5 زخمی ہوئے۔ عہدیداروں نے آج یہ بات بتائی۔ تعلقہ کے علاقہ واگرا میں واقع کے جی یئی ڈی سی کے صنعتی علاقہ میں سین زیل فارما کیم میں جمعہ کی رات تقریباً 10 بجے یہ دھماکہ پیش آیا۔ کیمیکل فیکٹری جو صرف ایک سال قبل قائم کی گئی میں خام کیمیائی مادے تیار کیے جاتے تھے۔ سب ڈویژنل مجسٹریٹ منیشا منانی نے یہ بات بتائی۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ ری ایکٹر کی ٹانکی تکڑے تکڑے ہوگئی اور اس کے تکڑے فیکٹری میں دور دور تک پھیل گئے۔ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اکشیاراج مکھوانا نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ دھماکے میں 5 افراد ہلاک اور دیگر 5 زخمی ہوئے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ مہلوکین کی شناخت آمود کے رہائشی جئے دیپ مہیش بھائی پٹیل اور بھاوک دلیپ کمار واسوضلع گیرسوماتھ کے مقام تلالہ کے وروند تلاویا اترپردیش کے انکیت ہرلال گوتم اور ارجن کمار رام سنگھ گوتم کی حیثیت سے کی گئی ہے۔

گریٹر نوئیڈا میں مشتبہ سمیت غذا کے سبب 5 افراد کی موت

سمیت غذا کے ایک مشتبہ کیس میں آج گریٹر نوئیڈا کے ایک دیہات میں ایک جوڑا اور اس کے تین بچے مردہ پائے گئے۔ پولیس نے یہ بات بتائی۔ پولیس کے مطابق 37 سالہ مہیش، اس کی 35 سالہ اہلیہ للیتا، 7 سالہ بیٹی مشتی اور دو بیٹے 11 سالہ لڈو اور 3 سالہ سکشت آج صبح دیہات ناگلاشری پدم میں مردہ پائے گئے۔ مقامی افراد اور مہیش کی ماں کے مطابق بادی النظر میں یہ سمیت غذا کا کیس ہے۔ کل رات وہ نوڈلس کھائے تھے۔ واقعہ کے بعد فارنسک عہدیدار اور محکمۂ فوڈ سیفٹی کے عہدیداروں کی ٹیم برسر موقع ثبوت اور غذا کے نمونے جمع کرنے پہنچی۔ پولیس واقعہ کی تحقیقات کا آغاز کرکے نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کی۔ پولیس نے بتایا کہ ہلاکتوں کے حقیقی اسباب کا ہنوز پتہ نہیں چلا ہے اور کہا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور فارنسک کے نتائج کی بنیاد پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ جیوار کے بی جے پی رکن اسمبلی دھیریندرا سنگھ جو جائے واقعہ کا دورہ کیے نے بتایا کہ انھوں نے اس المناک واقعہ کی اطلاع چیف منسٹر آفس کو دی ہے۔ افرادِ خاندان کے کھانے میں زہریلے مادوں کی موجودگی یا کسی اور سبب سے ہلاکتیں پیش آئی ہیں کا پتہ چلایا جائے گا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے پر اصل سبب کا پتہ چلے گا۔ انھوں نے ارکانِ خاندان کی بے وقت موت کو دلی صدمہ پہنچنے کا واقعہ قرار دیا۔

ایلون مسک کی کمپنی تیز رفتار انٹرنیٹ خدمات فراہم کرنے تیار

اسٹارلنک کا ضروری سرکاری منظوریوں کے ساتھ ہندوستان میں انفراسٹرکچر قائم کرنے کا اعلان

آوازِ تسنیم: ایلون مسک کی زیر قیادت کام کرنے والی کمپنی اسٹارلنک نے جمعہ کے روز کہا ہے کہ اس نے پانچ سال سے زائد عرصے تک ہندوستانی ریگولیٹرز، صنعت اور آپریٹرز کے ساتھ مل کر کام کیا ہے اور تمام ضروری سرکاری منظوریوں کے ساتھ ملک کے اندر مخصوص انفراسٹرکچر تیار کیا ہے، ساتھ ہی کمپنی نے ہندوستان میں تیز رفتار انٹرنیٹ خدمات فراہم کرنے کے لیے اپنی مکمل تیاری کا اعادہ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اسٹارلنک نے ریلائنس انڈسٹریز کے جمعہ کے روز جاری کردہ بیان کو بھی ٹیگ کیا جس میں مکیش امبانی کی زیر قیادت کمپنی نے سیٹلائٹ مواصلات کے شعبے میں اسٹارلنک سمیت دیگر حریفوں کا خیر مقدم کیا تھا لیکن اس بات پر زور دیا تھا کہ تمام کمپنیوں کو ہندوستانی قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اسٹارلنک 2022 سے ہندوستان میں کام کرنے کے لیے ریگولیٹری اجازت نامے حاصل کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، تاہم اسپیکٹرم کے الاٹمنٹ، قیمتوں کے تعین اور ممکنہ سکیورٹی خدشات کے باعث یہ عمل تاخیر کا شکار رہا ہے۔ اسٹارلنک نے ایکس پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے ہندوستان میں ریگولیٹرز، انڈسٹری اور آپریٹرز کے ساتھ پانچ سال سے زائد عرصے تک قریبی تال میل سے کام کیا ہے اور ملک ہی میں مخصوص سسٹمز، گیٹ ویز اور دیگر انفراسٹرکچر کا ایک پورا نیٹ ورک قائم کیا ہے تاکہ ہندوستانی انٹرنیٹ ٹریفک کو مکمل طور پر محفوظ طریقے سے سنبھالا جاسکے اور یہ سب کچھ ضروری سرکاری منظوریوں کے تحت کیا گیا ہے۔ کمپنی نے مزید کہا کہ وہ ہندوستان کو تیز رفتار انٹرنیٹ سے جوڑنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ جمعہ کے روز دونوں کمپنیوں کے مابین یہ مکالمہ ہندوستان کی سیٹلائٹ مواصلاتی مارکیٹ میں مسابقت کے حوالے سے جاری عوامی بحث کے دوران سامنے آیا ہے، جس میں ایلون مسک نے ملکی سیٹ کام کے ماحول پر سوالات اٹھائے تھے۔

تعلیم، روزگار اور احترام کیلئے ووٹ دیں: پرشانت کشور

آوازِ تسنیم: جن سوراج کے معمار اور بانکی پور کے ایم ایل اے پرشانت کشور نے ہفتہ کو کہا ہے کہ لوگوں کو ذات اور مذہب سے اوپر اٹھ کر اپنے اور اپنے بچوں کی تعلیم وروزگار اور اساتذہ کو اپنی عزت اور پے اسکیل کے لیے ووٹ دینا چاہیے۔ مسٹر کشور نے کہا کہ اب لوگوں کو طے کرنا ہے کہ وہ سمراٹ چودھری کے بے لگام نظام میں رہنا چاہتے ہیں یا اس پر روک لگانا چاہتے ہیں۔ جن سوراج کے معمار آج قانون ساز کونسل کے انتخابات کے پیش نظر گریجویٹ سمواد پروگرام میں شامل ہونے کے لیے نالندا پہنچے تھے۔ اس دوران انہوں نے بہار کے سیاسی نظام، وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کے حوالے سے وائرل ہونے والے اپنے مبینہ ادھورے بیان اور جن سوراج کے تعلق سے کیے جا رہے پروپیگنڈے سے متعلق سوالات کے جوابات دیے۔ مسٹر کشور نے وزیر اعلیٰ مسٹر چودھری کے حوالے سے وائرل ہونے والے اپنے ادھورے بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے مسٹر چودھری کی تعلیمی قابلیت اور ان کے خلاف قتل کے الزامات کا ذکر کرتے ہوئے اپنے سابقہ تبصرے کو دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے غلط کہا ہے تو سمراٹ حکومت ان کے خلاف مقدمہ درج کرا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تھانے میں ممبر اسمبلی اور ممبر پارلیمنٹ ہی یہ طے کرنے لگیں کہ کون ملزم ہے اور اسے گولی ماردی جائے، تو اسی بنیاد پر مسٹر چودھری کو بھی مجرم ٹھہرایا جاسکتا ہے۔

ایس پی کی مقبولیت سے آدتیہ ناتھ خوفزدہ
سماج وادی پارٹی ایم پی اودیش پرساد کا بیان

آوازِ تسنیم: سماج وادی پارٹی ایم پی اودیش پرساد نے آج یہاں الزام عائد کیا کہ ملک میں غیر معلنہ ایمرجنسی ہے۔ انھوں نے کہا کہ مطالبات کو منوانے کے لیے احتجاج کرنے والے قائدین اور کارکنوں کے خلاف سخت کارروائیاں کی جارہی ہیں۔ سماج وادی پارٹی کے سینئر قائد پرساد نے الزام عائد کیا ہے کہ چیف منسٹر اترپردیش یوگی آدتیہ ناتھ اپنے مقاصد اور مفادات کی تکمیل کے لیے احتجاجیوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت دے رہے ہیں۔ انھوں نے مزید بتایا کہ ہم کو اظہارِ خیال کی آزادی حاصل ہے جو کہ ایک بنیادی حق ہے۔ پرامن طور پر احتجاج کرنے والوں کے خلاف استبدادی اقدامات کیے جارہے ہیں۔ چیف منسٹر اترپردیش یوگی آدتیہ ناتھ کو سماج وادی پارٹی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوف ہے۔ وہ سماج وادی پارٹی صدر اکھلیش یادو اور پارٹی کے دوسرے قائدین کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوفزدہ ہو رہے ہیں۔ اب جب کہ ریاست میں 2027 میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں، چیف منسٹر اترپردیش پارٹی کو کمزور کرنے اور مسائل ومشکلات میں مبتلا کرنے کے لیے ممکنہ کوشش کر رہے ہیں۔

بچوں کیلئے انٹرنیٹ تک رسائی بنیادی حق' سپریم کورٹ کا پابندی سے انکار

◆ والدین کے کنٹرول اور سوشل میڈیا پر 'چائلڈ موڈ' نافذ کرنے پر زور
◆ جنسی استحصال پر مبنی مواد کی تشہیر اور ترسیل روکنے کے لیے قومی ڈیٹا بیس بنانے کی ہدایت

آوازِ تسنیم: سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ انٹرنیٹ تک رسائی اور اس کے استعمال کا حق بچوں کو بھی حاصل ہے اور محض عمر کی بنیاد پر انٹرنیٹ کے استعمال پر مکمل پابندی عائد نہیں کی جاسکتی۔ عدالت نے کہا کہ بچوں کے حقوق اور ان کی حفاظت ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں، بلکہ بچوں کو دونوں کا حق حاصل ہے۔ اس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر بچوں کے تحفظ کے لیے والدین کے کنٹرول کو سخت بنانے، 'چائلڈ موڈ' جیسی سہولتیں فراہم کرنے اور بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق مواد کو ہٹانے کے مؤثر اقدامات پر زور دیا۔ جسٹس جے بی پاردی والا اور جسٹس کے وی چندرن پر مشتمل بنچ نے 15 اکتوبر کو بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم 'جسٹ رائٹس فار چلڈرن الائنس' اور ایک دوسرے درخواست گزار کی عرضیوں پر سماعت کے دوران یہ ریمارکس دیے۔ عرضیوں میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس بچوں کے جنسی استحصال اور بدسلوکی سے متعلق مواد کی اطلاع ہندوستانی حکام کو دینے کی اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں۔ عدالت نے آئین کی دفعہ 21 اور دفعہ (a)(1)(19) کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انٹرنیٹ تک رسائی اور اس کے استعمال کا حق ہر فرد کا بنیادی حق ہے۔ بنچ کے مطابق، عمر سے قطع نظر بچوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہیں اور انہیں مکمل طور پر اس حق سے محروم کرنا درست نہیں ہوگا۔ عدالت نے اس دلیل کی جانب بھی توجہ دلائی کہ محض قانونی پابندی عائد کردینے سے بچے انٹرنیٹ کا استعمال بند نہیں کردیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی آن لائن سرگرمیوں کو محفوظ بنانے کے لیے مؤثر ضابطہ جاتی نظام تیار کیا جائے۔ بنچ نے کہا کہ بچوں کی حفاظت اور ان کی آزادی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں؛ بچوں کو دونوں حقوق ملنے چاہئیے۔ سماعت کے دوران عدالت نے بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق مواد کی بار بار تشہیر اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے میں متعلقہ حکام اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کی مبینہ ناکامی پر بھی تشویش ظاہر کی۔ عدالت نے کہا کہ متاثرین کے تحفظ کے لیے سنجیدہ اقدامات کا فقدان افسوس ناک ہے۔ درخواست گزاروں نے سوشل میڈیا پر ایسے مواد کی تشہیر، ری ڈائریکٹ لنکس اور ویب سائٹس کے ذریعے اس کی ترسیل کے واقعات کی نشان دہی کی تھی۔ عدالت نے مرکزی حکومت کو ہدایت دی کہ بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق تصدیق شدہ مواد کی شناخت اور اسے ہٹانے میں مدد کے لیے ڈیجیٹل شناختی علامات اور یو آر ایل پر مشتمل ایک قومی ڈیٹا بیس تیار کیا جائے۔ اس کے علاوہ حکومت کو پرسیپچوئل ہیش میچنگ، یو آر ایل کی فہرست سازی اور دیگر تکنیکی اقدامات کے ذریعے ایسے مواد کی شناخت اور اسے ہٹانے کے لیے رہنما اصول اور معیاری عملی طریق کار وضع کرنے کی ہدایت بھی دی گئی۔ عدالت نے واضح کیا کہ انٹرنیٹ پر غیر رضامندی کے ساتھ تیار یا پھیلایا جانے والا جنسی استحصال اور بدسلوکی پر مبنی مواد کسی بھی صورت قابل قبول نہیں، بالخصوص ایسے پلیٹ فارمس پر جہاں بچوں اور معاشرے کے دیگر کم عمر اور کمزور افراد کی آسانی سے رسائی ہوتی ہے۔

बलूच कार्यकर्ता ने बलूचिस्तान में तोड़फोड़ और अधिकारों के उल्लंघन को लेकर चिंता जताई

आवाज़ ए तसनीम



बलूचिस्तान/पाकिस्तान। 'द बलूचिस्तान पोस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार, बलूच कार्यकर्ता सम्मी दीन बलूच ने आरोप लगाया है कि बलूचिस्तान में लोगों को जबरन बेदखल किया जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं और जरूरी सामानों की आपूर्ति पर लंबे समय से पाबंदियां लगाई गई हैं। ये सब वहां के समुदायों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। 'द बलूचिस्तान पोस्ट' के मुताबिक, डॉ. दीन मुहम्मद बलूच (जिन्हें जबरन गायब कर दिया गया था) की बेटी सम्मी ने बताया कि दशकों से चले आ रहे विस्थापन ने हजारों परिवारों को उखाड़ फेंका है। इससे वे अपनी पुश्तैनी जमीन, घरों और आय के पारंपरिक स्रोतों से अलग हो गए हैं।

2026 में दर्ज की गई घटनाएं मस्तुंग से लेकर ग्वादर तक फैली हुई हैं, जिनमें शूर पारोद, नुश्की, चगाई और खारन जैसे इलाके शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कुछ निवासियों को अपने घर खाली करने का आदेश दिया गया है, जबकि अन्य बस्तियों को ध्वस्त कर दिया गया है, जिससे परिवारों को दूसरी जगह जाने के लिए बहुत कम समय मिला है। ज़ेहरी, मशके और ज़मुरान में लंबे समय तक कर्फ़्यू और सड़कें बंद रहने के कारण, महीनों तक लोगों को भोजन और अन्य जरूरी चीजें नहीं मिल पाईं, जिससे वहां के निवासियों की मुश्किलें और बढ़ गईं।

सम्मी ने दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों की नाजुक स्थिति पर प्रकाश डाला। इनमें से कई परिवार भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के खर्च के लिए छोटी खेती, फसलों और पशुधन पर निर्भर हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अचानक विस्थापन से लोगों का आर्थिक आधार खत्म हो जाता है। ऐसे में परिवारों को नई और अनजान जगहों पर रहने की जगह, रोजगार और अपने बच्चों के लिए स्कूल खोजने में भारी संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा का हवाला देकर अधिकारी विस्थापित लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।

उन्होंने कहा कि अगर लोगों को कहीं और बसाया जाता है, तो उन्हें पर्याप्त सुरक्षा, रहने के लिए वैकल्पिक घर, आजीविका के साधन और जरूरी सेवाएं मिलनी चाहिए। साथ ही, उन्हें सुरक्षित वापस लौटने की गारंटी भी दी जानी चाहिए। 'द बलूचिस्तान पोस्ट' के अनुसार, सम्मी ने आगे कहा कि समुदायों को उनकी पुश्तैनी जमीन से हटाना और उनकी वापसी के बारे में कोई स्पष्टता न देना, महज एक मानवीय संकट से कहीं बड़ी बात है। इससे उनकी अपनी पहचान, संस्कृति, सामुदायिक रिश्तों को बचाए रखने और अपने भविष्य पर नियंत्रण रखने की क्षमता कमजोर हो जाती है।

'द बलूचिस्तान पोस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार, अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने बताया कि जब परिवारों को उनके पारंपरिक परिवेश से उखाड़कर किसी अनजान शहर में बसने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वे अक्सर अकेलेपन और अनिश्चितता का सामना करते हैं, खासकर तब जब उनके साथ कोई रिश्तेदार या समुदाय का समर्थन न हो।

यूरोप के 6 देशों में शिक्षा-महंगाई पर प्रदर्शन

फ्रांस में आगजनी-लूटपाट, इटली में स्कूलों पर कब्जा किया, ग्रीस में संसद के सामने बैठे आंदोलनकारी

आवाज़ ए तसनीम



यूरोप के 6 देशों में पढ़ाई का बढ़ता खर्च, बेरोजगारी और महंगे घरों के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। फ्रांस में प्रदर्शनकारियों ने दुकानों में लूटपाट की और कई सरकारी इमारतों में आग लगा दी।

इटली में छात्रों ने कई स्कूलों पर कब्जा कर लिया। ग्रीस में छात्र हॉस्टल की कमी और बढ़ते किराए के विरोध में संसद के सामने टेंट लगाकर बैठे हैं। बेल्जियम और अल्बानिया में भी प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई और गिरफ्तारियां की गईं।

फ्रांसः 140 शहरों में प्रदर्शन, 1800 गिरफ्तार

फ्रांस में स्कूलों की खराब हालत, शिक्षकों की कमी और बढ़ती महंगाई के विरोध में 17 अक्टूबर को 140 शहरों में प्रदर्शन हुए। करीब 8 लाख लोग सड़कों पर उतरे। इसमें छात्र संगठनों के साथ ट्रेड यूनियन और कर्मचारी भी शामिल थे।

पेरिस, मार्सेई और बोर्डो समेत कई शहरों में तोड़फोड़ और लूटपाट हुई। लीमोज में 143 साल पुराने ऐतिहासिक सिटी हॉल में आग लगा दी गई और कई गाड़ियों को जला दिया गया।

18 अक्टूबर तक करीब 1800 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं, 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों, सुरक्षाकर्मियों और दमकलकर्मियों के घायल होने की खबर है।

प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हिंसा की निंदा की है। सरकार का कहना है कि कुछ हिंसक समूहों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का फायदा उठाया।

इटलीः स्कूलों की हालत पर 30 अक्टूबर को हड़ताल का ऐलान

इटली में छात्र शिक्षा पर कम सरकारी खर्च, जर्जर स्कूलों और पढ़ाई के बढ़ते खर्च के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रोम और ट्यूरिन समेत कई शहरों में छात्रों ने स्कूलों पर कब्जा कर लिया।

16 अक्टूबर को रोम में हजारों छात्र शिक्षा मंत्रालय की ओर मार्च करते हुए पहुंचे। उन्होंने शिक्षा मंत्री ग्यूसेपे वाल्दितारा के फैसलों का विरोध किया।

इससे पहले हुए प्रदर्शनों में पुलिस के साथ झड़प और पथराव की घटनाएं भी हुई थीं। अब छात्र संगठन इस आंदोलन से कर्मचारियों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने 30 अक्टूबर को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है।

छात्रों की मांग है कि शिक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ाया जाए, स्कूलों की हालत सुधारी जाए और सस्ते हॉस्टल उपलब्ध कराए जाएं।

स्पेनः बढ़ते किराए के खिलाफ प्रदर्शन

स्पेन में महंगे घरों और बढ़ते किराए के खिलाफ आंदोलन कई शहरों में फैल गया है। राजधानी मैड्रिड के सोल चौक पर प्रदर्शनकारी कई दिनों से टेंट लगाकर बैठे हैं।

सितंबर के आखिर में 87 साल की एक बुजुर्ग महिला को किराया बढ़ने के कारण घर से निकाल दिया गया था। इसके बाद आंदोलन तेज हो गया।

प्रदर्शनकारी किराए पर नियंत्रण लगाने, लोगों को घरों से निकालने पर रोक लगाने और सस्ते सरकारी मकान बनाने की मांग कर रहे हैं।

किराएदारों के संगठन और आवास अधिकारों के लिए काम करने वाले समूह आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। मैड्रिड के अलावा दूसरे शहरों में भी रैलियां निकाली गई हैं।

प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज की सरकार ने आवास संकट दूर करने के लिए कदम उठाने की बात कही है, लेकिन प्रस्तावित उपायों पर राजनीतिक सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच, 29 नवंबर को समय से पहले चुनाव कराने का ऐलान भी किया गया है।

ग्रीसः हॉस्टल की कमी के खिलाफ टेंट लगाकर प्रदर्शन

ग्रीस की राजधानी एथेंस में छात्रों ने संसद के सामने टेंट लगाकर प्रदर्शन किया। छात्र हॉस्टल की कमी, महंगे किराए और पढ़ाई के बढ़ते खर्च से परेशान हैं। छात्र संगठनों के मुताबिक, देश में बहुत कम छात्रों को हॉस्टल मिल पाते हैं।

करीब 96% छात्रों को हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलती, जबकि पिछले 10 साल में कमरों का किराया तीन गुना हो गया है। कुछ छोटे कमरों का मासिक किराया 600 यूरो तक पहुंच गया है।

प्रदर्शनकारी किराए की सीमा तय करने, सरकारी हॉस्टल बनाने, स्कॉलरशिप बढ़ाने और यूनिवर्सिटीज का बजट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन का नेतृत्व छात्र संगठन कर रहे हैं।

बेल्जियमः शिक्षा बजट में कटौती के खिलाफ गुस्सा

बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में शिक्षा बजट में कटौती और सुधारों के विरोध में छात्रों ने मार्च निकाला। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की और पुलिस पर चीजें फेंकीं। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया।

18 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पांच पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई।

प्रदर्शन का नेतृत्व छात्र संगठन कर रहे हैं। सरकार ने हिंसा की निंदा की है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बात कही है।

अल्बानियाः प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग

अल्बानिया की राजधानी तिराना में महंगी पढ़ाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और यूनिवर्सिटीज की खराब हालत के खिलाफ छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। हजारों युवा 15 अक्टूबर को शिक्षा मंत्रालय के बाहर जुटे और प्रधानमंत्री एदी रामा के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। सरकारी इमारतों और बैंकों में भी आग लगा दी गई।

उन्होंने छात्रों से बातचीत की पेशकश की, लेकिन तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई की बात भी कही। उनका कहना है कि हिंसा से अल्बानिया के यूरोपीय संघ में शामिल होने की कोशिश को नुकसान पहुंच सकता है।

टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में 5 राउंड फायरिंग, एक्टर सुरक्षित

लॉरेंस गैंग ने जिम्मेदारी ली; वायरल ऑडियो में सलमान खान को खत्म करने की धमकी

आवाज़ ए तसनीम



मुंबई। एक्टर टाइगर श्रॉफ पर रविवार शाम 7 बजे मुंबई में फायरिंग हुई। घटना में टाइगर को कांच के टुकड़े लगे हैं और गनपाउडर से हाथ जलने के निशान हैं। वहीं, टाइगर के ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति को गोली लगी है। फिलहाल दोनों खतरे से बाहर हैं।

टाइगर जब फुटबॉल खेलकर लौट रहे थे तभी उनकी कार जुहू के पुष्पा पार्क के पास रुकी। यहां उन्हें देखने के लिए भीड़ जमा थी। तभी एक बाइक पर सवार तीन लोग वहां पहुंचे और टाइगर की कार पर 5 राउंड फायरिंग की। घटना जुहू पुलिस स्टेशन से महज 350 मी. दूर हुई।

हमले के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट और ऑडियो वायरल हो रहा है। इसमें लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली। लिखा कि सलमान खान के साथ काम करने वाले का यही अंजाम होगा।

ऑडियो में खुद को अनिल पंडित बताने वाला शख्स सलमान खान को भी धमका रहा है। कह रहा है कि सलमान और उसके परिवार को खत्म कर देंगे। वे चाहे जितनी सिक्योरिटी में रहें।

पुलिस ने ड्राइवर के बयान दर्ज किए

मुंबई पुलिस ने हमले में घायल टाइगर के ड्राइवर फिरदौस का बयान दर्ज किया है।

टाइगर का सलमान के साथ अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं

लॉरेंस गैंग की पोस्ट वायरल होने के बाद बॉलीवुड में टाइगर श्रॉफ और सलमान खान के साथ काम करने की चर्चाएं होने लगीं। हालांकि, ट्रेड सूत्रों के मुताबिक, ऐसी किसी फिल्म की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है।

टाइगर हाल ही में निर्देशक रेमो डिसूजा की अनटाइटल्ड एक्शन फिल्म की शूटिंग पूरी कर चुके हैं। वह आगे जान्हवी कपूर और लक्ष्य के साथ राज मेहता के निर्देशन में बन रही 'लग जा गले' फिल्म करने वाले हैं।

टाइगर पर फायरिंग के आरोपी अंधेरी स्टेशन पर बाइक छोड़कर भागे

टाइगर पर फायरिंग के मामले में शामिल तीन आरोपी वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल अंधेरी रेलवे स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गए। मुंबई पुलिस ने बाइक जब्त कर ली है।

पुलिस बाइक के रजिस्ट्रेशन और चेसिस नंबर की जांच कर उसके बारे में जानकारी जुटा रही है। आरोपियों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

प्रत्यक्षदर्शी महिला बोली- पहले हमें लगा पटाखे फोड़ रहे हैं

प्रत्यक्षदर्शी महिला ने बताया- मैंने लड़के को फायरिंग करते हुए अपनी आंखों से देखा। देखने में वह मुझे एक छोटा लड़का ही लगा। मुझे लगा कि दिवाली की वजह से या फिर टाइगर से मिलने की खुशी में वह पटाखे फोड़ रहा है।

जब घर के बाकी लोगों ने आवाज सुनी, तो उन्हें भी यही लगा कि पटाखे फूट रहे हैं। वह बाइक से आया था या नहीं, यह मैंने नहीं देखा लेकिन वह वहीं रुका और उसने सीधे बंदूक से गोलियां चलानी शुरू कर दीं। यह देखते ही हम सब जान बचाकर घर के अंदर भाग गए।

शिंदे बोले- किसी भी गैंग की धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि टाइगर का किसी से कोई विवाद या झगड़ा नहीं था। इसके बावजूद एक युवा अभिनेता पर इस तरह जानलेवा हमला हुआ। टाइगर और उनकी मां घटना से काफी घबराए हुए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार टाइगर और अन्य सार्वजनिक हस्तियों के साथ खड़ी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिंदे ने कहा कि मुंबई पुलिस ऐसी घटनाओं और गैंगवार पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई करेगी।

इजराइल से ऑस्ट्रिया जा रही फ्लाइट को बम की धमकी

फाइटर जेट की निगरानी में इमरजेंसी लैंडिंग; 6 क्रू मेंबर समेत 57 लोग सवार थे

आवाज़ ए तसनीम



सोफिया। इजराइल से ऑस्ट्रिया जा रही ऑस्ट्रियन एयरलाइंस की फ्लाइट को बम की धमकी के बाद बुल्गारिया में उतारा गया।

एयरबस A320 रविवार रात तेल अवीव से वियना जा रहा था। खतरे की सूचना के बाद बुल्गारिया की वायुसेना ने विमान को एस्कॉर्ट करने के लिए स्खुल-29 लड़ाकू विमान भेजा।

विमान में 51 यात्री और छह क्रू सदस्य सवार थे। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

फ्लाइट तीन घंटे बाद बुल्गारिया में लैंड हुई

फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, ऑस्ट्रियन एयरलाइंस की फ्लाइट रविवार शाम 6:46 बजे तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट से रवाना हुई थी। विमान जब रोमानिया के ऊपर था तब इसे बुल्गारिया की राजधानी सोफिया की ओर मोड़ा गया।

करीब तीन घंटे बाद 9:10 बजे यह सोफिया के वासिल लेव्स्की एयरपोर्ट पर उतरा। बुल्गारिया के परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, अलर्ट मिलने के करीब 30 मिनट बाद विमान की सुरक्षा जांच शुरू हुई।

बुल्गारिया और इजराइली मीडिया ने बताया कि विमान को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। ऑस्ट्रियन एयरलाइंस ने भी खतरे की पुष्टि की है, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं दी।

6 दिन पहले भी इजराइल जा रही फ्लाइट को बम की धमकी मिली थी

अमेरिका के न्यूयॉर्क से तेल अवीव पहुंची डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट को भी 13 अक्टूबर को बम की धमकी मिली। विमान खाली कराकर तलाशी ली गई, लेकिन कोई विस्फोटक नहीं मिला।

इससे एक दिन पहले इंडोनेशियाई पायलट के कारण इजराइल ने इथियोपियन एयरलाइंस के कार्गो विमान को उतरने की मंजूरी नहीं दी थी। पायलट बदलने के बाद विमान को अनुमति मिली।

दरअसल सितंबर में फ्लाईदुबई की फ्लाइट में हुए हादसे के बाद इजराइल ने सुरक्षा नियम सख्त कर 11 देशों के पायलटों और क्रू पर रोक लगा दी है। इनमें अफगानिस्तान, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, नाइजर, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया और वेनेजुएला शामिल हैं। इन देशों के इजराइल से राजनयिक संबंध नहीं हैं।

पिछले महीने फ्लाईदुबई की फ्लाइट हाईजैक हुई थी

30 सितंबर को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में ओमान के पायलट ने विमान को हाईजैक कर लिया था। उसने दूसरे पायलट पर चाकू से हमला कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमलावर विमान को इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर गिराने की कोशिश कर रहा था।

हालांकि, कई यात्रियों ने बीच में आकर उसे रोक दिया और फाइटर जैट्स की निगरानी में विमान की सऊदी अरब के ताबुक एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इजराइली न्यूज चैनल 12 के मुताबिक, फ्लाईदुबई पर हमले के अगले दिन इजराइल के परिवहन मंत्रालय ने एयरलाइंस को पत्र भेजा था। इसमें कहा गया था कि दुश्मन देशों के नागरिकों को इजराइल जाने वाली उड़ानों में पायलट, क्रू मेंबर या यात्री के तौर पर सफर करने की अनुमति न दी जाए।

कोलकाता पंडाल में भगदड़

बारिश में सैकड़ों लोग दौड़कर अंदर घुसे, संकरे रास्ते में दबे, महिलाएं-बच्चे चीखने लगे; 19 मौतें, 5 ICU में भर्ती

आवाज़ ए तसनीम



कोलकाता। कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार रात भगदड़ के दो वीडियो सामने आए हैं। 27 सेकेंड के एक वीडियो में बारिश के बीच सैकड़ों लोग दौड़ते हुए पंडाल में घुसते दिख रहे हैं।

पंडाल के अंदर के एक अन्य वीडियो में संकरे रास्ते में लोगों की भारी भीड़ फंसी दिख रही है। लोग एक-दूसरे से सटकर खड़े थे और दबाव के कारण हिलने-डुलने तक की जगह नहीं थी। महिलाएं और बच्चे मदद के लिए चीख रहे थे। हादसे में 19 लोगों की मौत हुई, जबकि 25 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 5 मरीज ढ्ढष्ट में भर्ती हैं। पुलिस ने पूजा कमेटी के सचिव और उपाध्यक्ष समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन पर गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है।

बंगाल के पंडालों में खत्म होगी VIP पास सुविधा

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को कहा कि सरकार दुर्गा पूजा पंडालों में VIP गेट की व्यवस्था खत्म करने को अनिवार्य कर सकती है। खासकर लोकप्रिय और बड़े बजट वाले पूजा आयोजक आमतौर पर VIP पंडाल विजिटर्स के लिए अलग प्रवेश की व्यवस्था करते हैं। इन रास्तों पर आमतौर पर कम भीड़ रहती है। श्रद्धालुओं को प्रीमियम कीमत पर विशेष पास दिए जाते हैं, जिनके जरिए वे VIP गेट से पंडाल में प्रवेश करते हैं।

गिरफ्तार 7 लोगों को 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया

कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ के मामले में गिरफ्तार सात लोगों को पुलिस ने रविवार को स्थानीय अदालत में पेश किया। अदालत ने सभी को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

ऋतब्रत बनर्जी बोले- ये राजनीतिक पोस्टमार्टम का समय नहीं

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का समय नहीं है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी घटना के बाद राजनीतिक व्यवस्था के कुछ लोग आरोप-प्रत्यारोप में पूरी तरह उतर आए। राजनीतिक पोस्टमार्टम हो सकता है, लेकिन वह बाद में होना चाहिए। सबसे पहले कीमती जिंदगियां गई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया है कि क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। मैं उनसे सहमत हो सकता हूं या असहमत, लेकिन राजनीतिक पोस्टमार्टम के लिए अभी इंतजार करना चाहिए।

TMC ने घायलों को प्राइवेट अस्पताल शिफ्ट करने पर उठाए सवाल

भगदड़ के बाद घायलों को सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने पर विवाद खड़ा हो गया है। ममता के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रवक्ता और विधायक कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज शुरू होने के बाद घायलों को दूसरे अस्पताल में भेज दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इलाज के बीच मरीजों को क्यों शिफ्ट किया गया।

कुणाल घोष ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि अमित शाह के अस्पताल दौरे के दौरान सरकार की अच्छी छवि दिखाने के लिए घायलों को निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। उन्होंने आशंका जताई कि इससे मरीजों से मुलाकात करना और हादसे के बारे में उनकी बात जानना मुश्किल हो सकता है।

कोलकाता भगदड़ में बिहार के पिता-बेटे की मौत

कोलकाता भगदड़ के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर के अभिषेक कुमार श्रीवास्तव और उनके बेटे आयुष कुमार श्रीवास्तव की मौत हो गई।

अभिषेक की पत्नी निवा कुमारी भी उनके साथ थीं। मृतक के भाई राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि परिवार दुर्गा पूजा घूमने कोलकाता आया था। हालांकि, सीएम अधिकारी ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले 19 लोगों में एक बिहार का रहने वाला था।

सीएम बोले- भगदड़ की जांच रिपोर्ट डेढ़ महीने में सार्वजनिक करेंगे

सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कोलकाता भगदड़ की जांच हाईकोर्ट के मौजूदा जज करेंगे। कमेटी की सिफारिशें मिलने के एक से डेढ़ महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी। उन्होंने पिछली CPM और TMC सरकारों पर उनके कार्यकाल में गठित आयोगों की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने का आरोप भी लगाया। विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने अक्टूबर 2025 में भारी बारिश और दार्जिलिंग में हुई आपदा का जिक्र करते हुए पिछली सरकारों के कामकाज पर सवाल उठाए।





विशिष्ट पंजीकरण योजना-2026,मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया पत्रकारों के लिए विशेष आवास योजना का शुभारंभ

पत्रकारों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही राज्य सरकारःशर्मा

- अपने आशियाने का सपना होगा साकार, सुरक्षित-सुविधायुक्त फ्लैट्स की मिलेगी सौगात
- वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना एवं आरजेएचएस जैसी सुविधाओं से सुनिश्चित हो रही पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा
- पूंछरी का लौठा के पास विकसित हो रही सैटेलाइट सिटी में लाई जाएगी आवासीय योजना

जयपुर(नि.सं.)। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारिता केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक दायित्व, जनजागरण और राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण साधना है। उन्होंने अपने पत्रकारिता के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि वे पत्रकारों को होने वाली समस्याओं और कठिनाइयों को अच्छे से समझते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार पत्रकारों के सम्मान, संवेदनशीलता और कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आवासीय योजना के फेज-1 में 3 बीएचके फ्लैट पर कुल लागत में 15 लाख रुपये और 2 बीएचके फ्लैट पर कुल लागत में 12 लाख रुपये की विशेष छूट देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से अन्य संभागों में भी आवासीय योजनाएं लाई जाएंगी। उन्होंने भरतपुर में पूंछरी का लौठा के पास विकसित हो रही सैटेलाइट सिटी में भी नई आवासीय योजना लाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान में राजस्थान आवासन मंडल की विशिष्ट पंजीकरण योजना-2026 के तहत पत्रकारों के लिए विशेष आवास योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बजट में अधिस्वीकृत पत्रकारों को आवास उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई थी, जिसकी अनुपालना में जयपुर के इंदिरा गांधी नगर आवासीय योजना, सेक्टर-9, जगतपुरा में पत्रकारों के लिए फ्लैट्स का पंजीकरण शुरू किया गया है।



इस बहुमंजिला आवासीय योजना के तहत फ्लैट्स में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि पत्रकार साथियों को सुरक्षित और सुविधायुक्त आवासीय वातावरण मिल सके। उन्होंने कहा कि सकारात्मकता से जुड़ी पत्रकारिता ही अपनी सार्थकता सिद्ध करती है। राजस्थान की पत्रकारिता का इतिहास स्वाभिमान और गौरव का साक्षी रहा है। विजय सिंह पथिक और पंडित झाबरमल्ल शर्मा जैसे मनीषियों की परंपरा ने सामाजिक सुधार, जनजागरण और प्रदेश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

पत्रकार कल्याण की दिशा में उठाए महत्वपूर्ण कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले पौने तीन वर्षों में पत्रकारों के कल्याण के लिए अनेक पहल की हैं। स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण के लिए आयु सीमा और अनुभव में छूट देकर न्यूनतम पात्रता आयु 45 वर्ष तथा अनुभव 15 वर्ष निर्धारित किया गया, जिससे 31 प्रेस प्रतिनिधि लाभान्वित हुए हैं। अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 43 छात्रवृत्तियां दी गई हैं।

न्यूज इन बॉक्स



कानोड़िया पीजी महिला महाविद्यालय में डांडिया की धूम, 2000 छात्राओं ने गरबा-डांडिया से बांधा समां

जयपुर(नि.सं.)। जयपुर कानोड़िया पीजी महिला महाविद्यालय में 17 अक्टूबर को डांडिया उत्सव-2026 का भव्य आयोजन किया गया। रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजी लगभग 2,000 छात्राओं ने उत्सव में उत्साहपूर्वक भाग लिया और डांडिया की खनक से माहौल को जीवंत बना दिया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. सीमा अग्रवाल ने प्राध्यापिकाओं के साथ डांडिया उत्सव में भाग लिया और छात्राओं को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दीं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध गायिका मधु भाट ने अपनी संगीतमय प्रस्तुति से समां बांध दिया। लाइव म्यूजिक की धुनों पर छात्राओं ने जमकर डांडिया किया। इस आयोजन के लिए नृत्यम डांस क्लब द्वारा 10 दिवसीय डांडिया कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला में छात्रा एवं नृत्य निर्देशक पलक वाधवा ने छात्राओं को डांडिया नृत्य का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षित छात्राओं ने 'ढोली रा', 'गरबे की रात' और 'चौगाड़ा तारा' सहित विभिन्न गुजराती एवं बॉलीवुड गीतों पर मनमोहक प्रस्तुति दी।



एआई के दौर में सिर्फ ओरिजनल कंटेंट वाले पत्रकार रहेंगे

पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में डिजिटल जर्नलिज्म पर हुआ सेशन, 21 छात्र सम्मानित हुए

जयपुर(नि.सं.)। पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता के बदलते परिदृश्य को लेकर विशेष सेशन हुआ। यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की ओर से हुए इस सेशन के एक्सपर्ट दैनिक भास्कर डिजिटल के स्टेट एडिटर किरण राजपुरोहित रहे। पत्रकारिता का बदलता परिदृश्य = पारंपरिक से डिजिटल की ओर बदलाव विषय पर किरण राजपुरोहित ने छात्रों को डिजिटल जर्नलिज्म से जुड़े गुर सिखाए। इस दौरान ट्रेनी जर्नलिस्ट्स के तौर पर निकाय चुनावों के कवरेज में अहम योगदान निभाने वाले पत्रकारिता के छात्रों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी की प्रो प्रेजिडेंट डॉ. मंजरी राय, फैकल्टी ऑफ डिजाइन एंड आर्टस के डीन डॉ.जितेंद्र शर्मा, प्रोक्टर प्रमेंद्र मीणा, दैनिक भास्कर डिजिटल के सीनियर मैनेजर- एडिटोरियल विपिन कुमार सहित विभाग के अन्य फैकल्टीज और छात्र मौजूद रहे।



दिया कुमारी ने अमृता हाट की महिला उद्यमियों को दिया डिजिटल मंत्र

डिजिटल ज्ञान से बनेगी आर्थिक उड़ानःदिया कुमारी

जयपुर(नि.सं.)। महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशालय महिला अधिकारिता की ओर से जयपुर के जवाहर कला केन्द्र में चल रहे राज्य स्तरीय अमृता हाट में भाग ले रही स्वयं सहायता समूहों की महिला उद्यमियों के लिए शनिवार को रंगायन सभागार में एक विशेष डिजिटल मार्केटिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की। उन्होंने वहां उपस्थित महिलाओं को डिजिटल तकनीक अपनाकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने तथा आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया।

वित्तीय और डिजिटल साक्षरता जरूरी

उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा



कि व्यापार में महिलाओं को वित्तीय रूप से साक्षर होना आवश्यक है। आज के समय में केवल उत्पाद बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही बाजार तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पिछली बार राज्य स्तरीय अमृता हाट की विजिट के दौरान ज्ञात हुआ कि एसएचजी की महिलाएं अपने उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री बहुत कम करती हैं। इसी को ध्यान में रखकर हमने महिला अधिकारिता निदेशालय के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग के लिए यह वर्कशॉप आयोजित की है। एसएचजी की महिलाओं का वित्तीय साक्षरता के साथ ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग करना आसान होगा।

वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल

उन्होंने महिला उद्यमियों की सराहना करते हुए कहा कि अब महिलाएं नौकरी मांगती नहीं बल्कि कई अन्य महिलाओं को नौकरी देती हैं यह महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा दिए गए मंत्र 'वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल' के अनुसार कार्य करना है।

मुख्य सचिव से मिला निरीक्षण दल

चंबल नदी में अवैध खनन रोकने के लिए सख्त एवं प्रभावी मॉनिटरिंग हो सुनिश्चितःमुख्य सचिव



जयपुर(नि.सं.)। चंबल नदी में अवैध बजरी खनन की रोकथाम के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के संबंध में वन विभाग के अधिकारियों की कमेटी ने चंबल क्षेत्र के कोटा, बूंदी सवाई-माधोपुर, धौलपुर एवं करौली जिलों का निरीक्षण कर मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास से मुलाकात की। मुख्य सचिव ने निर्देशों की पालना में अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण आनंद कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री पी. के. उपाध्याय एवं अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री के. सी. अरुण प्रसाद के दल ने कोटा,बूंदी सवाई-माधोपुर,धौलपुर एवं करौली जिलों में चंबल नदी में अवैध खनन के स्थानों की जमीनी स्थिति का निरीक्षण कर मुख्य सचिव को क्षेत्र की वस्तु स्थिति से अवगत करवाया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण श्री आनंद कुमार ने कोटा, बूंदी एवं सवाई-माधोपुर जिलों के चंबल नदी में अवैध खनन क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने जिला टास्क फोर्स के अधिकारियों की बैठक कर अवैध खनन रोकथाम के प्रभावी एवं सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए।



सीमेंट फैक्ट्री में चोरी करने वाला गिरोह पकड़ा

जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार

जोधपुर(वि.सं.)। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मारवाड़ सीमेंट फैक्ट्री में हुई बड़ी चोरी का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 6 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। ये चोर फैक्ट्री से 6 लाख रुपये का सामान पिकअप गाड़ी में भरकर ले गए थे। पुलिस ने चोरी गया पूरा माल भी बरामद कर लिया गया है।

दीवार फांदकर स्टोर में घुसे थे चोर

पुलिस के अनुसार, घटना 12 अक्टूबर 2026 की है। घोड़ावट स्थित मारवाड़ सीमेंट फैक्ट्री की दीवार फांदकर अज्ञात बदमाशों ने स्टोर में धावा बोला था। चोरों ने स्टोर में रखे कीमती पावर केबल, एल्युमिनियम प्लेट, गैस कटर और रेगुलेटर समेत करीब 6 लाख रुपये का सामान चुराया और उसे पिकअप में लादकर फरार हो गए थे।

कोटा के विभिन्न इलाकों में शिविर भी होंगे आयोजित

आरएसजीएल का कोटा में पीएनजी से जोड़ने का अभियान शुरुःएमडी पाटनी



जयपुर(नि.सं.)। राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस द्वारा हरित उर्जा को बढ़ावा देने के लिए 17 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक परिवारों को पाइपलाइन से घरेलू प्राकृतिक गैस सुविधा से जोड़ने का अभियान शुरू किया गया है। आरएसजीएल के प्रबंध निदेशक विनय पाटनी ने बताया कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा एलपीजी कनेक्शनों को डीपीएनजी कनेक्शनों में परिवर्तित करने पर जोर देते हुए एलपीजी फ्री जोन बनाने पर फोकस किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पीएनजीआरबी ड्राइव 3 के विशेष अभियान के तहत अधिक से अधिक घरों को पीएनजी सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य है। पीएनजी एक अत्यधिक सुरक्षित, किफायती एवं सुविधाजनक ईंधन है। इसमें पानी के नल की तरह घर घर पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस पहुँचती है और 24×7 दिन उपलब्ध रहती है। बार बार गैस सिलिंडर बुक करने व बदलने का झंझट नहीं रहता है। इस त्यौहारी मौसम पर आरएसजीएल ने 31 दिसंबर 26 तक कोटा में घरों में पीएनजी सुविधा से जुड़ने वाले नए परिवारों के लिए 5000 पॉइंट प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है। एमडी विनय पाटनी से आरएसजीएल के अधिकारियों से वर्चुअल बैठक में बताया कि भारत सरकार के पीएनजीआरबी द्वारा समूचे देश में अभियान चलाकर नागरिकों को जागरुक करने और डीपीएनजी सुविधा से जोड़ने का निर्णय किया गया है।



हनुमानगढ़ में दो महिलाएं हेरोइन के साथ पकड़ी

ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत 51.37 ग्राम अवैध हेरोइन जब्त, जांच जारी

हनुमानगढ़(वि.सं.)। हनुमानगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत दो महिलाओं को 51.37 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई हनुमानगढ़ जंक्शन थाना क्षेत्र में डीएसटी टीम की सूचना पर की गई। पुलिस अधीक्षक आदित्य ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

गिरफ्तार महिलाओं की पहचान फिरोजपुर निवासी रीना रानी (26) और मुक्तसर निवासी सिमरजीत कौर (32) के तौर पर हुई है। दोनों पंजाब की रहने वाली हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 08/21 के तहत केस दर्ज किया है। महिला पुलिस थाना हनुमानगढ़ की चंद्रकला मामले की जांच कर रही हैं।

कोहरे के कारण दिसंबर से फरवरी तक छह ट्रेनें प्रभावित

अजमेर-अमृतसर ट्रेन दोनों तरफ से कैंसिल, सियालदह और डिब्रूगढ़ रूट की चार ट्रेनों के फेरे भी घटाए

जयपुर(नि.सं.)। सर्दियों में कोहरे के कारण कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। उत्तर पश्चिम(नॉर्थ-वेस्टर्न) रेलवे ने दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 तक दो ट्रेनों को पूरी तरह कैंसिल करने और चार ट्रेनों के फेरे कम करने का फैसला किया है। इनमें अजमेर-अमृतसर, अजमेर-सियालदह और लालगढ़-डिब्रूगढ़ रूट की ट्रेनें शामिल हैं। नॉर्थ-वेस्टर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि कोहरे के दौरान सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए यह फैसला लिया गया है।



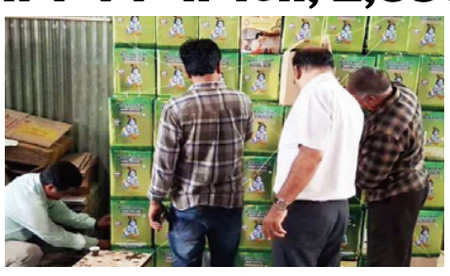
अजमेर-अमृतसर ट्रेन दोनों तरफ से कैंसिल रहेगी। वहीं, अजमेर-सियालदह और लालगढ़-डिब्रूगढ़ ट्रेनें तय तारीखों पर नहीं चलेंगी।

ये दो ट्रेनें पूरी तरह कैंसिल रहेंगी 1. ट्रेन नंबर 19611, अजमेर-अमृतसर, इस ट्रेन की दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 तक कुल 26 ट्रिप कैंसिल रहेगी। दिसंबर 2026= 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 और 31 जनवरी 2027= 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 और 30 फरवरी 2027= 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 और 27 2. ट्रेन नंबर 19614, अमृतसर-अजमेर, इस ट्रेन की दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 तक कुल 26 ट्रिप कैंसिल रहेगी। दिसंबर 2026= 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 और 27 जनवरी 2027: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 और 31 फरवरी 2027: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 और 28

शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान | झोटवाड़ा स्थित एसके एंटरप्राइजेज के प्लांट पर कार्रवाई

बेकरी शॉर्टनिंग' के नाम पर विभिन्न ब्रांडों के तहत उत्पाद का निर्माण एवं बिक्री किए जाने का मामला, 2,699.2 किलो बेकरी शॉर्टनिंग सीज

जयपुर(नि.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन तथा प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती गायत्री राठौड़ के निर्देशन में आमजन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 'शुद्ध आहार्ङ्गमिलावट पर वार' अभियान के तहत कार्रवाई लगातार जारी है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण श्री अविचल चतुर्वेदी के निर्देशानुसार, अतिरिक्त आयुक्त श्री भगवत सिंह के मार्गदर्शन एवं संयुक्त आयुक्त श्री वी.पी. शर्मा के पर्यवेक्षण में केंद्रीय खाद्य सुरक्षा दल ने जयपुर के झोटवाड़ा स्थित



एम/एस एसके एंटरप्राइजेज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर कार्रवाई की गई।

बेकरी शॉर्टनिंग के नाम पर तैयार हो रहा था उत्पाद

निरीक्षण के दौरान 'बेकरी शॉर्टनिंग' के नाम पर चंचल, नेहा गोल्ड और जय श्री गोल्ड सहित विभिन्न ब्रांडों के तहत उत्पाद का निर्माण एवं बिक्री किए जाने का मामला सामने आया। विभाग ने उत्पाद की प्रकृति, लेबलिंग और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर जांच शुरू की है।

2,699.2 किलो उत्पाद सीज

खाद्य सुरक्षा दल ने नमूने लेने की कार्रवाई के साथ बाजार में बिक्री के लिए तैयार 2,699.2 किलोग्राम बेकरी शॉर्टनिंग को सीज किया। विभाग की सतर्कता से त्योहारी सीजन में इस उत्पाद की बिक्री पर जांच पूरी होने तक रोक लगाई गई है। उत्पाद की गुणवत्ता और नियमानुसार लेबलिंग से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है।

खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं

अतिरिक्त आयुक्त श्री भगवत सिंह ने कहा कि खाद्य पदार्थों के नाम या लेबल की आड़ में नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि जांच के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मिलावट पर रोक लगाने के लिए अभियान के तहत निरीक्षण एवं नमूनीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी।

स्वामी और प्रकाशक रमाकांत गोस्वामी एवं मुद्रक ताराचंद कुमावत द्वारा महारानी प्रिन्टर्स, 17 मां वैष्णो देवी नगर, कालवाड़ रोड़ जयपुर छपवाकर/मुद्रित कर, 10 MA, आईजी नगर, जगतपुरा,जयपुर, राजस्थान - 302017 से प्रकाशित किया। संपादकः रमाकान्त गोस्वामी, उप संपादक - मोनिका शर्मा, पीआरजीआई नं. RJBIL/25/A1815 ब्रांच ऑफिसः 18k3, पंकज सिंघवी मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर-302002, मो. नं. 7610866001, हैल्प लाईन नं.: 8946840063, ईमेल आईडीः tasneemtv.official @gmail.com, वेबसाइटः www.tasneemtv.com (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी. आर. पी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तदायी), किसी भी वाद-विवाद से निपटने के लिए न्यायालय जयपुर मान्य होगा।